कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

ज्येष्ठ–ज्येष्ठ 2083, जून 2026

नरेंद्र मोदी

सरकार के 12 वर्ष

स्वदेशी गतिविधियां

जिला विचार/प्रशिक्षण वर्ग

सचित्र झलक

अत्तूर, तमिलनाडु

अकोला, महाराष्ट्र

विश्व पर्यावरण दिवस

जौनपुर, उ.प्र.

बोकारो, झारखंड

कोलकता, पश्चिम बंगाल

गोड्डा, झारखंड

स्वदेशी व्यापारी मंच, नागपूर

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

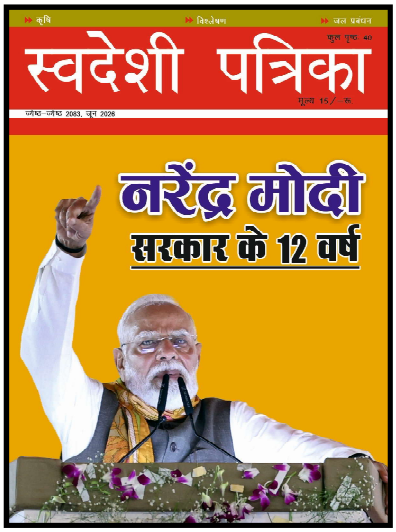

वर्ष–34, अंक–6
ज्येष्ठ–ज्येष्ठ 2083 जून 2026

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 36-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–06

सरकार के 12 साल
नरेंद्र मोदी अब भी अजेय क्यों बने हुए हैं!
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा–2
मोदी सरकार के 12 वर्षः भारत के पुनर्निर्माण की गाथा और विकसित भारत का मार्ग
डॉ. धनपत राम अग्रवाल

11 आवरण कथा–3
मोदी सरकार के 12 सालः परम वैभव के लिए उठे सधे हुए कदम
अनिल तिवारी

14 आवरण कथा–4
मोदी युग में डिजिटल बदलाव
शिवनंदन लाल

16 आत्मनिर्भरता
आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में स्वदेशीः आत्मनिर्भरता से रणनीतिक एकीकरण की ओर
प्रो. दीपक शर्मा

18 विचार
डिजिटल व्यसन–वृत्ति
विनोद जौहरी

20 मुद्दा
सोने के आयात को रोकने की कवायद
स्वदेशी संवाद

22 पुस्तक समीक्षा
पुण्यभूमि नागदा, नागदा विप्रकुल और परमेष्ठी राज्य मेवाड़
प्रो. नंदिनी सिन्हा कपूर

24 विभूति
सेवा, समरसता और राष्ट्रधर्म की अमर ज्योति – लोकमाता अहिल्याबाई
प्रो. रूबी मिश्रा

26 योग
विश्व योग दिवस – योगस्य चित्त वृत्ति निरोध
डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

28 शिक्षा
शिक्षा के मंदिर में 'कोचिंग वॉर' और दांव पर लगता मासूम छात्रों का भविष्य
अजय कुमार

30 रिपोर्ट
आती–जाती सत्ता के साथ बदलती नेताओं की वफादारी
संजय सक्सेना

32 जयंती
बालासाहब देवरसः समाज एवं देशसेवा को समर्पित
हेमेन्द्र क्षीरसागर

पाठकनामा

बेहतर आर्थिक विकल्प से ही रूकेगी अफीम की खेती

मणिपुर इस समय बाहरी घुसपैठ, राजनीतिक अस्थिरता और अवैध अफीम (पोस्ता) की खेती के कारण पैदा हुए एक बहुआयामी संकट का सामना कर रहा है। भारत और म्यांमार के बीच की 400 किलोमीटर लंबी खुली और असुरक्षित सीमा ने अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी और हथियारों की तस्करी को बढ़ावा दिया है। म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट और वहां जारी आंतरिक संघर्ष ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के खुलासे के अनुसार, एनएससीएन–आईएम के "चीन–म्यांमार मॉड्यूल" ने भारत में घुसपैठ करने के लिए प्रतिबंधित संगठनों का समर्थन किया, जो यह दर्शाता है कि कैसे बाहरी राजनीति देश की आंतरिक अस्थिरता से जुड़ी हुई है।

हाल के दिनों में आई कमी के बावजूद, अफीम की खेती अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशंस सेंटर (एमएआरएसएसी) के आंकड़ों के मुताबिक, अफीम की खेती का क्षेत्र साल 2022–23 के 16,632.29 एकड़ से घटकर साल 2023–24 में 11,288.07 एकड़ रह गया है, जो कि 32.13 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। साल 2017 से 2024 के बीच, मणिपुर सरकार ने 19,135 एकड़ अफीम की फसलों को नष्ट किया है। इसके बावजूद, चंदेल, चुराचाँदपुर और सेनापति जैसे पहाड़ी जिलों में अभी भी अवैध खेती की जा रही है।

मणिपुर के युवा इस समय गंभीर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में यहाँ बेरोजगारी दर 22.9 प्रतिशत है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत महज 9.9 प्रतिशत है। आर्थिक तंगी से पैदा हुई यही हताशा युवाओं को अफीम की खेती की ओर धकेलती है, जहाँ ड्रग कार्टेल (माफिया) उन्हें 500 से 1,000 रुपये प्रति दिन की मजदूरी देते हैं। आर्थिक तनाव के बावजूद, युवा अब बिना किसी सामाजिक संकोच या शर्म के छोटे–मोटे काम और सड़क किनारे व्यावसायिक उद्यम (स्ट्रेट वेंचर्स) शुरू कर रहे हैं।

कांगपोकपी के नागरिक संगठनों ने साल 2026 से अफीम की खेती को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का संकल्प लिया है, जो जनभावनाओं के सुधार को दर्शाता है। हालांकि, जब तक किसानों को कमाई के व्यावहारिक और कानूनी विकल्प नहीं दिए जाते, तब तक केवल कड़े कानून लागू करके अफीम की खेती को पूरी तरह रोकना मुमकिन नहीं है; इसके लिए वास्तविक आर्थिक विकल्प प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

विजित कुमार, क्षेत्र मीड़िया प्रमुख, पूर्वोत्तर भारत, स्वदेशी जागरण मंच

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

जी–7 देशों की पूंजी, भारत की प्रतिभा और वैश्विक दक्षिण के देशों की भागीदारी को मिलाकर, हम संपर्क सहभागिता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 'इंटरनेशनल मोबिलाइज़ेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड' (इम्पैक्ट) बनाने पर भी विचार कर सकते हैं।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

भारत अमरीका के साथ प्रस्तावित व्यापारिक समझौते को तब तक लागू नहीं कर सकता, जब तक उसे प्रतिद्वंदी देश की तुलना में किसी तरह का सीधा फायदा नहीं मिलता है।

पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री, भारत

समय के साथ भारत को हम जिस स्थान पर देखना चाहते हैं, उसे एक विश्वगुरु के रूप में वहां पहुंचाने के लिए आज की आधुनिक समस्याओं का समाधान अपने पुरातन ज्ञान को साथ लेकर करना होगा।

सुनील आम्बेकर, अ.भा. प्रचार प्रमुख, रा.स्वं.संघ

हमें यह कहना पड़ रहा है कि निर्दोष भारतीय नाविकों की हत्या केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं है, यह नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। ऐसी घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय कानून की अहमियत कम होगी और दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

बैरंग क्यों लौटा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल?

पिछले लंबे समय से अमरीका के ही नहीं, भारत के वार्ताकार भी यह कहते रहे हैं कि भारत–अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि इस बाबत भारत और अमरीका में अभी भी गतिरोध बना हुआ है। इसी सप्ताह के अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर), जो समझौते को अंतिम रूप देने हेतु कई दिनों तक भारत में थे, इस काम को अंजाम पहुँचाये बिना वापस अमरीका लौट चुके हैं। यह बात मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले फ़रवरी माह में भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के मसौदे यानी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे। उस मसौदे पर हस्ताक्षर के बाद, भारतीय पक्ष के द्वारा जो बातें रखी गई थी, अमेरिकी प्रशासन द्वारा उनसे उलट बयानबाजी के कारण देश में भारी असमंजस की स्थिति बन गई थी। विपक्षी राजनीतिक दलों और मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। सब से पहली बात तो यह थी कि अमेरिकी पक्ष बारम्बार यह बात कह रहा था कि भारत ने रूस से तेल नहीं ख़रीदने की वादा अमरीका से किया है, जबकि मसौदे में उसका ज़िक्र भी नहीं था। इसके आलवा अमरीकी पक्ष यह दावा कर रहा था कि भारत ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वो अमेरिका से आगे पाँच वर्षों में 500 अरब डॉलर का साजोसामान ख़रीदेगा, जबकि समझौते के मसौदे में 500 अरब डॉलर का सामान ख़रीदने की केवल इरादा भर ही व्यक्त किया गया था। इसके अलावा कृषि पदार्थों के आयात के संदर्भ में भी मसौदे से इतर कई बातों का ज़िक्र अमरीकी पक्ष कर रहा था। स्वाभाविक तौर पर राजनयिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए हर बात खंडन करना भी भारत सरकार के लिए औचित्यपूर्ण नहीं होता, लेकिन सरकार द्वारा समय–समय पर अपना पक्ष दोहराया जाता रहा।

भारत और अमेरिका द्वारा, जिसमें मसौदे या फ्रेमवर्क पर सहमति के हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लगाए जा रहे मनमर्जी के टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसलिए व्यापार विशेषज्ञों का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में भारत और अमरीका के बीच व्यापार के मसौदे पर सहमति का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब फरवरी में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के लिए अंतरिम रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब स्थिति यह थी कि अमेरिका ने कई देशों से होने वाले आयात पर काफी ज्यादा पारस्परिक शुल्क लगा रखे थे। प्रस्तावित रूपरेखा के तहत, भारत पर टैरिफ का बोझ घटकर लगभग 18 प्रतिशत होने की उम्मीद थी, जबकि कई प्रतिस्पर्धी देशों को अपेक्षाकृत ज्यादा टैरिफ दरों का सामना करना पड़ता। इससे अमेरिकी बाज़ार में भारतीय निर्यातकों को एक बड़ा प्रतिस्पर्धी फ़ायदा मिलता। इसलिए इस संबंध में दोबारा वार्ता करना ज़रूरी हो जाता है। यह तर्क काफ़ी प्रभावशाली लगता है। इससे भारत के सामने एक सवाल यह है कि जिन फायदों की पक्की गारंटी अमेरिका अब नहीं दे सकता, उस पर भरोसा कैसे किया जाए। यही कारण है कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यह कह रहे हैं कि भारत–अमरीका व्यापार समझौता लगभग तैयार है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर तब तक नहीं हो सकते जब तक भारत को अन्य देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं होगा। परिणामस्वरूप, फरवरी की रूपरेखा के पीछे का आर्थिक आधार मूल रूप से बदल गया है। जिन मान्यताओं के आधार पर यह रूपरेखा तैयार की गई थी, वे अब सही नहीं हैं। इसलिए, जब तक बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार शर्तों पर फिर से बातचीत नहीं की जाती, तब तक अंतरिम समझौते के लिए बनी पिछली रूपरेखा को काफी हद तक बेकार माना जा सकता है, क्योंकि इससे भारत को वह अपेक्षित विशेष लाभ नहीं मिल रहा है।

फरवरी 2026 के फ्रेमवर्क समझौते के बावजूद, कुछ मुद्दे अनसुलझे ही रह गए थे। इनमें कृषि बाज़ार तक पहुँच, मांसाहारी दूध एवं उत्पादों का आयात, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक सामानों पर टैरिफ में कटौती, डिजिटल व्यापार और डेटा गवर्नेंस, बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दे, 'उत्पत्ति के नियम' (रूल्स ऑफ़ ऑरिजिन), पेशेवरों की आवाजाही और वीज़ा से जुड़ी चिंताएँ शामिल हैं। गौरतलब है कि अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों, स्वास्थ्य उपकरणों और शराब पर टैरिफ कम करे। भारत इन टैरिफ को कम न करने पर अड़ा हुआ है, जिसके दो कारण हैं – एक तो कृषि और डेयरी सेक्टर में लोगों की आजीविका का सवाल है, और दूसरी वजह रणनीतिक औद्योगिक विकास से जुड़ी है।

डिजिटल व्यापार और डेटा से जुड़े नियम भी समझौते में रुकावट डालने वाले अहम मुद्दे हैं। भारत डेटा को एक रणनीतिक संसाधन मानता है और भविष्य में नीति निर्माण से संबंधित अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहता, जबकि अमेरिका डेटा लोकलाइज़ेशन (डेटा को देश के देश में ही रखने) की शर्तों का विरोध करता है और डेटा को सीमा पार ले जाने की आज़ादी चाहता है। समझना होगा कि भारत जो भविष्य में डिजिटल महाशक्ति बनने की और अग्रसर है इस बात के लिए तैयार कई हो सकता है?

अमेरिका चाहता है कि भारत उसके उद्योगों को अधिक मज़बूत पेटेंट सुरक्षा दे, जबकि भारत के लिए दवाओं की सस्ती उपलब्धता बनाए रखना चाहता और अपने प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए पेटेंट कानूनों के तहत लचीलापन बना रहे। इसके अतिरिक्त अमेरिकी प्रशासन लगातार अपने वीसा और इमीग्रेशन क़ानूनों को पहले से अधिक कठोर करता जा रहा है, जिससे भारत सरकार ही नहीं जानता में भी भारी रोष है। लेकिन इन मुद्दों का लेशमात्र भी जिक्र व्यापार समझौते के मसौदे में नहीं था।

अमेरिका राष्ट्रपति और अमेरिका प्रशासन द्वारा रूस के तेल ख़रीदने पर भारत पर प्रतिबंध लगाने और कभी भारत को रूस से तेल ख़रीदने के लिए अनुमति देने के संबंध में बयानबाजी की जाती रही है, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि रूस से तेल ख़रीदना या नहीं ख़रीदना अमरीका की मर्ज़ पर निर्भर है। यदि देखा जाए तो वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वास्तविकता तो यह है कि वर्ष (2026) में अभी तक रूस से तेल की ख़रीद, पिछले वर्ष (2025) में इस अवधि में तेल की ख़रीद से कहीं अधिक है; और जून माह में रूस से प्रति दिन 25. 5 लाख टन तेल ख़रीदा जा रहा है, जो केवल रिकॉर्ड ही नहीं, भारत के कुल तेल आयात का लगभग आधा है।

नरेंद्र मोदी अब भी अजेय क्यों बने हुए हैं!

26 मई 2014 को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और पहली पूर्ण गैर–कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया। जहां आज़ादी के बाद के शुरुआती तीन दशकों में भारत की आर्थिक विकास दर 3 से 4 प्रतिशत के बीच रही, वहीं पश्चिमी एशिया और दूसरी जगहों के छोटे देशों ने तकनीकी तरक्की के साथ–साथ बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास किया। जहां भारत को एक विकासशील देश माना जाता रहा, वहीं ये छोटे देश "एशियन टाइगर्स" के तौर पर मशहूर हो रहे थे।

गरीबी कम होने की रफ़्तार भी बहुत प्रभावशाली नहीं थी। एक खास ढांचे के आधार पर गरीबी का पहला आकलन 1973–74 में किया गया; जब योजना आयोग ने गरीबी रेखा की अवधारणा पेश की , जिसके मुताबिक 54.9 प्रतिशत आबादी इसके नीचे रह रही थी। हालांकि समय के साथ गरीबी रेखा की परिभाषाएं बदलती रहीं, लेकिन 2012–13 में भी 21.9 प्रतिशत आबादी, यानी 269.3 मिलियन (26.93 करोड़) लोग, गरीबी रेखा से नीचे माने जाते थे। इस बीच, वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के मुताबिक, जिसमें 2012–13 में रोज़ाना 1. 25 अमेरिकी डालर से कम कमाने वालों को घोर गरीबी में रहने वाला माना गया था, तब दुनिया के 1.2 अरब गरीब लोगों में से एक–तिहाई, यानी 40 करोड़ लोग, भारत में थे।

हालांकि, 2025 तक इसे बढ़ाकर 2.15 अमेरिकी डालर प्रति दिन कर दिया गया था। वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के आधार पर घोर गरीबी में रहने वाली कुल आबादी का हिस्सा घटकर सिर्फ़ 2.3 प्रतिशत रह गया है। वर्ल्ड बैंक की ताजा परिभाषा के तहत में 3 अमेरिकी डालर प्रति दिन के हिसाब से भी देखा जाए तो यह आंकड़ा सिर्फ़ 5.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसे निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हासिल हुई है।

आज भारत और दुनिया भर में गरीबी की एक ऐसी परिभाषा मौजूद है जो इस घोर गरीबी से आगे जाती है, यानी "बहुआयामी गरीबी"। इसे मापने में दस पैमाने शामिल हैं –

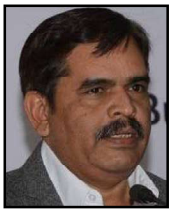

सर्वे लगातार दिखाते हैं कि इतने सालों में सरकार और प्रधानमंत्री, दोनों की लोकप्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

जिनमें दो शिक्षा से जुड़े, दो स्वास्थ्य से, और बाकी छह में आवास, बिजली, स्वच्छता, खाना पकाने के लिए साफ़ ईंधन, पीने का पानी और संपत्ति का मालिकाना हक से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अनुसार, 2015–16 और 2019–21 के बीच, सिर्फ़ पाँच सालों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 0.117 से घटकर 0.069 हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बहुआयामी गरीबी 2013–14 में 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में अनुमानित 11.28 प्रतिशत हो गई, जो एक दशक में लगभग 18 प्रतिशत अंकों की कमी को दर्शाता है।

दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि भारत में न केवल घोर गरीबी में बल्कि बहुआयामी गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी आई है। आम तौर पर, कई आर्थिक विशेषज्ञ यह तर्क देते हैं कि यदि आर्थिक विकास के दौर में गरीबी कम करने के प्रयासों के तहत संसाधनों के पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो विकास की गति धीमी हो सकती है। इसलिए, उनका मानना है कि आर्थिक विकास के चरणों के दौरान पुनर्वितरण को प्राथमिकता देना उचित नहीं है। इस विचार को मानने वाले अर्थशास्त्री, जो मुक्त व्यापार और मुक्त बाज़ार के समर्थक भी हैं, उनमें न केवल वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के विशेषज्ञ शामिल हैं, बल्कि प्रो. जगदीश भगवती और उनके सह–लेखक प्रो. अरविंद पनगढ़िया जैसी बड़ी हस्तियाँ भी इसी श्रेणी में आती हैं।

ऐसे अर्थशास्त्रियों की दलीलों के बावजूद, न केवल भारत ने आर्थिक विकास दर ऊंचा रखा, बल्कि बहुआयामी और अत्यधिक गरीबी को कम करने में भी बड़ी सफलता हासिल की। कोविड–19 के कारण एक साल के झटके के बावजूद, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत की वास्तविक

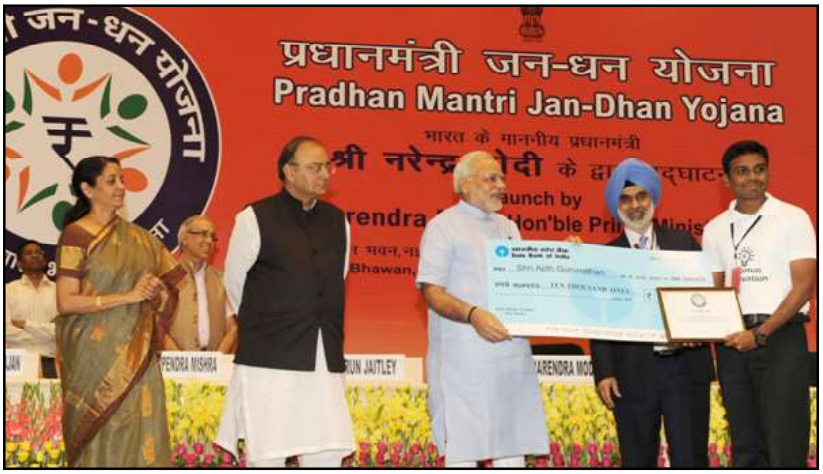

जन–धन खाते खुलने के बाद, उन्हें आधार (यूआईडी) और मोबाइल फ़ोन नंबरों से जोड़ा गया; नतीजतन, अब पूरी कल्याणकारी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पैसे के बीच में ही गायब होने या चोरी होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

जीडीपी (जीडीपी) लगभग 7.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ती रही।

हमें यह भी पहचानना होगा कि देश में असमानता और गरीबी को कम करने में कौन सी नीतियां असरदार साबित हुईं। यह समझना ज़रूरी है कि जहां आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में गरीबी कम होने की रफ़्तार बहुत धीमी थी, वहीं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गरीबी कम करने की दिशा में कैसे बड़ी प्रगति हुई, जिससे विकास पहले की तुलना में कहीं ज्यादा समावेशी हो गया।

वित्तीय समावेशन

आज़ादी और 2014 के बीच विकास की कई कोशिशों के बावजूद, देश में वित्तीय समावेशन के मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसका सबूत यह है कि 2014 और 2026 के बीच 580 मिलियन (58 करोड़) जन धन खाते खोले गए। और इन जन धन खातों में कुल 3 लाख करोड़ रूपये जमा हो गए थे। जन धन खाते ज़ीरो–बैलेंस खाते होते हैं, यानी इन्हें खोलने के लिए किसी शुरुआती जमा राशि की ज़रूरत नहीं होती।

वित्तीय समावेशन का एक और पहलू 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (डीबीटी) है। पहले, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित फंड का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ सही लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता था। जन–धन खाते खुलने के बाद, उन्हें आधार (यूआईडी) और मोबाइल फ़ोन नंबरों से जोड़ा गया; नतीजतन, अब पूरी कल्याणकारी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पैसे के बीच में ही गायब होने या चोरी होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन का एक और पहलू 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) है। पहले, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित फंड का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार के कारण सही लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता था। हालाँकि, जन–धन खाते खुलने के बाद, उन्हें आधार (यूआईडी) और मोबाइल

फ़ोन नंबरों से जोड़ा गया; नतीजतन, अब पूरी कल्याणकारी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पैसे के बीच में ही गायब होने या चोरी होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रक्रिया को 'जैम त्रय' के नाम से जाना जाता है, जिसमें जन–धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी शामिल हैं, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता के दम पर हासिल किया है।

महिलाओं के लिए खासः आवास, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, बिजली और पानी

आज़ादी से लेकर 2014 तक के सफर की एक बहुत बड़ी सच्चाई यह थी कि 2014 में भी देश में 12.3 करोड़ लोग कच्चे (अस्थायी) घरों में रहते थे, जबकि 31.7 करोड़ लोग अर्ध–स्थायी घरों में रहते थे। इसके विपरीत, सिर्फ़ पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ और शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाए गए हैं, और उसके अलावा 1.2 करोड़ घर या तो मंजूर हो चुके हैं या बन रहे हैं।

खुले में शौच करने की मजबूरी को लंबे समय से देश के लिए एक बड़ा कलंक माना जाता था। यह संतोष की बात है कि 2014 के बाद से देश भर में 12.8 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे खुले में शौच की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान हो गया है। आज, देश में लगभग पूरी तरह से बिजली पहुँच चुकी है, और 'हर घर नल से जल' योजना के तहत ज्यादातर इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध हो गया है। स्वच्छ ईंधन की बात करें तो, जहाँ 2014 में केवल 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, वहीं अब यह संख्या 34 करोड़ से ज़्यादा हो गई है; खास बात यह है कि इनमें से 10 करोड़ नए

जीडीपी ग्रोथ के साथ-साथ, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां कई क्षेत्रों में साफ़ तौर पर दिखती हैं। सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, डिजिटल पेमेंट, स्पेस टेक्नोलहजी में बड़ी तरक्की और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम; ये सभी विकास कार्य बहुत अहम रहे हैं।

कनेक्शन 'उज्ज्वला योजना' के तहत दिए गए, जिसके ज़रिए गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ़्त सिलेंडर और गैस स्टोव उपलब्ध कराए गए। आवास, पानी, बिजली, स्वच्छता सुविधाएँ और एलपीजी कनेक्शन ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिनसे पूरे समाज और खासकर गरीबों को फ़ायदा हुआ है। हालाँकि, महिलाओं का सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण हुआ है, क्योंकि शौचालय, पानी और एलपीजी कनेक्शन मिलने से वंचित परिवारों की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में न सिर्फ़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बल्कि कानूनों के ज़रिए सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया है, जिससे महिलाओं – और खासकर मुस्लिम महिलाओं – की ज़िंदगी बदल गई है।

15 से 80 साल और उससे ज्यादा उम्र की मुस्लिम महिलाएं हमेशा इस डर में जीती थीं कि उनके पति कभी भी 'तलाक़–तलाक़–तलाक़' कहकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं और उन्हें एक मिनट के लिए भी घर में रहने नहीं दिया जाएगा। एक कानून बनाकर इस काम को अपराध घोषित करने से मुस्लिम महिलाएं हमेशा के लिए इस डर से आज़ाद हो गई हैं।

गौरतलब है कि इस सरकार द्वारा शीघ्रता से महिला आरक्षण करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण में बाधा डालने के कारण महिलाओं के बारे में लोगों की सोच पर बड़ा असर पड़ा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की ज्यादा वोटिंग ने असंतोष का संकेत दिया, जिससे ममता बनर्जी की टीएमसी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा।

जीडीपी ग्रोथ के साथ–साथ, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां कई क्षेत्रों में साफ़ तौर पर दिखती हैं। सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, डिजिटल पेमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम; ये सभी विकास कार्य बहुत अहम रहे हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ा हुआ कद एक मज़बूत और आत्मविश्वास से भरी राष्ट्रीय उपस्थिति को दिखाता है।

इन बातों का सरकार के प्रति लोगों की सोच पर सकारात्मक असर पड़ा है। शायद यही वजह है कि सर्वे लगातार दिखाते हैं कि इतने सालों में सरकार और प्रधानमंत्री, दोनों की लोकप्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।

विपक्ष को भी इससे एक ज़रूरी सबक लेना चाहिए। बिना किसी ठोस आधार के आलोचना करने या बेकार के मुद्दों पर सरकार का विरोध करने के बजाय, एक सोच–समझकर बनाया गया और भरोसेमंद रोडमैप पेश करने की ज़रूरत है। ऐसे रोडमैप में देश के सामने मौजूद अहम सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का समाधान होना चाहिए और आगे की तरक्की के लिए सार्थक विकल्प भी होने चाहिए, जो कि अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ❑❑

भारत के पुनर्निर्माण की गाथा और विकसित भारत का मार्ग

भूमिका

वर्ष 2014 भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारम्भ हुई नई विकास यात्रा ने शासन, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, सामाजिक कल्याण और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 2026 में जब यह यात्रा बारह वर्षों का पड़ाव पार कर चुकी है, तब इसका मूल्यांकन केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए।

इन बारह वर्षों में भारत ने विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। लगभग 1.84 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बन चुका है। किन्तु किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन केवल आर्थिक आकार से नहीं किया जा सकता। विकास की गुणवत्ता, उसकी समावेशिता, उसकी स्थिरता तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। मोदी सरकार के बारह वर्षों का मूल्यांकन इसी संतुलित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।

विकास का विस्तृत परिदृश्य

भारत आज पारंपरिक विकास मॉडल से आगे बढ़कर वह एक आधुनिक, डिजिटल और नवाचार–आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। कोविड महामारी जैसी अभूतपूर्व चुनौती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया

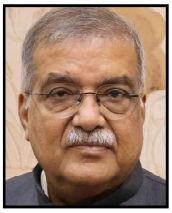

पिछले बारह वर्षों की यह यात्रा केवल शासन परिवर्तन की कहानी नहीं है; यह भारत के पुनर्निर्माण, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की गाथा है।

– डॉ. धनपतराम अग्रवाल

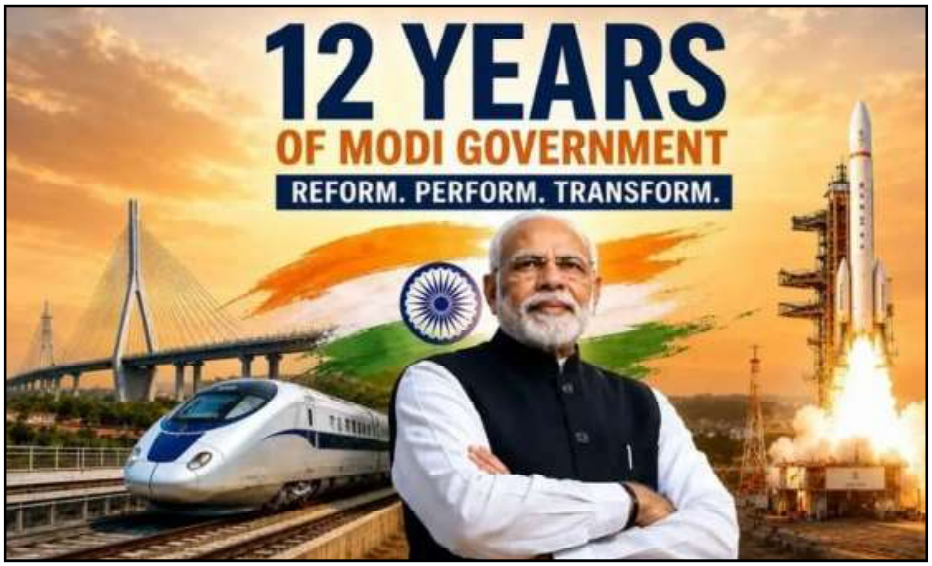

है। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विभिन्न वैश्विक एजेंसियाँ भारत को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन मान रही हैं। सेवाक्षेत्र, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अवसंरचना निवेश ने विकास की नई संभावनाएँ उत्पन्न की हैं।

अवसंरचना क्रांति : विकास की आधारशिला

पिछले बारह वर्षों की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि भारत की अवसंरचना क्रांति रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों का तीव्र विस्तार, एक्सप्रेसवे नेटवर्क का निर्माण, समर्पित मालवाहक गलियारों की स्थापना, रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदेभारत ट्रेनों का विस्तार तथा बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास ने देश की आर्थिक क्षमता को नई गति प्रदान की है।

जहाँ एक समय भारत की विकास यात्रा अवसंरचनात्मक बाधाओं से प्रभावित होती थी, वहीं आज लॉजिस्टिक दक्षता, क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक सुगमता में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देता है। पूँजीगत व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि ने रोजगार, निर्माण गतिविधियों तथा निवेश वातावरण को भी सुदृढ़ किया है। यह केवल सड़क, रेल और पुल निर्माण की कहानी नहीं है; यह भारत की उत्पादक क्षमता के पुनर्निर्माण की कहानी है।

डिजिटल भारत : विश्व के लिए एक मॉडल

जनधन, आधार और मोबाइल की त्रयी ने भारत में शासन और वित्तीय समावेशन की परिभाषा बदल दी है।

जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ने सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाकर पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि की।

चंद्रयान-३ की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों में भी भारत उच्च स्तरीय वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है। सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और राष्ट्रीय एआई मिशन भविष्य के भारत की तकनीकी नींव तैयार कर रहे हैं।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आज भारत की सबसे बड़ी डिजिटल उपलब्धियों में से एक है। प्रतिदिन होने वाले करोड़ों डिजिटल लेन–देन ने भारत को नकदी–प्रधान अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर किया है।

कोविन प्लेटफॉर्म, डिजिलॉकर, ओएनडीसी और अकाउंट एग्रीगेटर जैसी पहलों ने यह सिद्ध किया है कि भारत केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीकी समाधान प्रदान करने वाला राष्ट्र भी बन सकता है।

सामाजिक कल्याण की नई संरचना

किसी भी विकास मॉडल की सफलता का अंतिम मापदंड यह होता है कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा या नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्धता में क्रांतिकारी सुधार किया है।

उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया, जबकि आयुष्मान भारत योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की।

इन योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा के उस आधार को मजबूत किया है जिस पर समावेशी विकास की इमारत खड़ी की जा सकती है।

स्टार्टअप और नवाचार अर्थव्यवस्था

भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, नवाचार को प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और नीति सुधारों ने युवाओं में उद्यमशीलता की नई ऊर्जा उत्पन्न की है।

फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप वैश्विक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

चंद्रयान–3 की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों में भी भारत उच्च स्तरीय वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है। सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और राष्ट्रीय एआई मिशन भविष्य के भारत की तकनीकी नींव तैयार कर रहे हैं।

वैश्विक मंच पर भारत का उदय

पिछले बारह वर्षों में भारत की वैश्विक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जी–20 की सफल अध्यक्षता, अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलाने की पहल, क्वाड की सक्रियता, भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा तथा वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत की भूमिका ने उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊँचाई प्रदान की है।

योग, भारतीय संस्कृति, प्रवासी भारतीय समुदाय तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत की सॉफ्ट पावर को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।

आज विश्व भारत को केवल एक विशाल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय साझेदार और उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है।

उपलब्धियों के बीच अधूरा एजेंडा

इन उपलब्धियों के बावजूद कुछ गंभीर चुनौतियाँ हमारे सामने हैं।

निजी निवेश की गति अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँची है। विदेशी निवेश के सकल आँकड़े उत्साहजनक दिखाई देते हैं, किन्तु शुद्ध विदेशी निवेश में गिरावट चिंता का विषय है। यदि आर्थिक विकास का प्रमुख आधार केवल सार्वजनिक निवेश बन जाए, तो दीर्घकाल में उसकी स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इसलिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

असमानता और समावेशी विकास की चुनौती

भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावशाली रही है, किन्तु आय और संपत्ति का वितरण अभी भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। समाज के निचले वर्गों के जीवन स्तर में सुधार अवश्य हुआ है, किन्तु संपत्ति का संकेंद्रण शीर्ष वर्गों में अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से बढ़ा है। समावेशी विकास का अर्थ केवल गरीबी उन्मूलन नहीं, बल्कि अवसरों की समान उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था भी है। आर्थिक वृद्धि तभी टिकाऊ बन सकती है जब उसका लाभ व्यापक समाज तक पहुँचे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार का भविष्य

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आने वाले दशक का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी तत्व बनने जा रही है।

भारत का आईटी और बीपीओ क्षेत्र करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। किन्तु एआई आधारित स्वचालन पारंपरिक रोजगार संरचनाओं को चुनौती दे रहा है।

नई तकनीकें कुछ रोजगार समाप्त करेंगी, लेकिन साथ ही नए अवसर भी उत्पन्न करेंगी। चुनौती यह है कि भारत अपने युवाओं को इन नए अवसरों के लिए समय रहते तैयार कर सके।

एक व्यापक राष्ट्रीय पुनः कौशल (रेसकिलिंग) और कौशल उन्नयन (अपस्किलिंग) अभियान समय की आवश्यकता है।

तकनीकी सम्प्रभुता और अनुसंधान की आवश्यकता

21वीं शताब्दी में आर्थिक शक्ति का आधार केवल पूँजी नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी है।

भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, किन्तु दुर्लभ खनिजों, उन्नत सेमीकंडक्टर, एआई चिप्स, उच्च प्रदर्शन संगणना, क्लाउड अवसंरचना तथा क्वांटम तकनीक जैसे क्षेत्रों में अभी भी बाहरी निर्भरता बनी हुई है।

अनुसंधान एवं विकास पर भारत का व्यय अभी भी प्रमुख नवाचार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे तकनीकी उपभोक्ता से तकनीकी निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

विश्वविद्यालयों, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को नई ऊँचाइयों तक ले जाना होगा।

विकसित भारत 2047 : संकल्प से सिद्धि तक

विकसित भारत 2047 केवल आर्थिक प्रगति का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण का संकल्प है।

भारत के पास विशाल युवा शक्ति, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, तकनीकी क्षमता, उद्यमशीलता और वैश्विक स्वीकार्यता जैसे अनेक सकारात्मक तत्व हैं। किन्तु इन संभावनाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने के लिए निरंतर सुधार, नवाचार और सुशासन की आवश्यकता होगी।

आने वाले दो दशकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता निर्णायक भूमिका निभाएँगे।

उपसंहार

मोदी सरकार के बारह वर्षों का मूल्यांकन करते समय यह स्वीकार करना होगा कि भारत ने अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन का अनुभव किया है। अवसंरचना निर्माण की गति, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार, वैश्विक मंचों पर बढ़ती प्रतिष्ठा तथा नवाचार और उद्यमशीलता के क्षेत्र में नई ऊर्जा—ये सभी उस परिवर्तन के प्रमाण हैं जिसने भारत की विकास यात्रा को नई दिशा प्रदान की है। फिर भी राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। यह किसी एक सरकार, एक चुनाव या एक दशक की उपलब्धि नहीं होता। यह पीढ़ियों के सामूहिक पुरुषार्थ, दूरदृष्टि और राष्ट्रीय संकल्प का परिणाम होता है।

भारत आज एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहाँ वह विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। इसके लिए आवश्यक है कि उपलब्धियों पर संतोष करने के बजाय उन्हें नई ऊँचाइयों तक ले जाने का साहस दिखाया जाए। यदि विकास, सुशासन, नवाचार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता का यह प्रवाह निरंतर बना रहा, तो वर्ष 2047 का भारत केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं होगा, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक राष्ट्र बन सकता है।

वास्तव में, पिछले बारह वर्षों की यह यात्रा केवल शासन परिवर्तन की कहानी नहीं है; यह भारत के पुनर्निर्माण, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की गाथा है। मंज़िल अभी दूर है, किन्तु दिशा स्पष्ट है, और यही किसी भी महान राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। ❑❑

परम वैभव के लिए उठे सधे हुए कदम

विश्व बैंक की ताजा–ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी, रूस, यूक्रेन तथा मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया के अनेक देश विकास की दौड़ में सुस्त पड़ गए हैं, कई देशों की ग्रोथ निगेटिव है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से कुलांचे भर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया भर के विकास का इंजन बन रहा है। वैश्विक मंदी और चुनौतियों के बावजूद भारत में औसतन 6.5 से 7.5 प्रतिशत के बीच की शानदार वृद्धि दर बनाए रखी है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में भारत को वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच एक 'उज्जवल स्थान' के रूप में चिन्हित किया गया है।

यह वृद्धि केवल एक आंकड़ा भर नहीं है और न ही यह उपलब्धि किसी जादू की छड़ी से हासिल हुई है, बल्कि यह कुशल नेतृत्व में बढ़ते निवेश, रोजगार सृजन, उद्यमिता, स्वावलंबन और आर्थिक अवसरों के विस्तार का प्रमाण है। वर्ष 2013–14 में जहां देश की प्रति व्यक्ति आमदनी लगभग 79,118 रुपए प्रतिवर्ष थी, आज बढ़कर 2.05 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक की हो गई है। बीते 12 वर्षों में भारत ने राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को प्रतिष्ठित करते हुए आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के नए आयाम विकसित किए हैं।

दुनिया भर के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ कालखंड ऐसे रहे हैं जो केवल शासन परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की संस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के लिए याद किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते बारह वर्षों का दौर ऐसा ही एक कालखंड है। यह केवल एक प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल की कहानी नहीं है, बल्कि उस भारत की कहानी है जिसने नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई पहचान के साथ स्वयं को स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता के उस विश्वास का प्रमाण है जो बार–बार लोकतांत्रिक

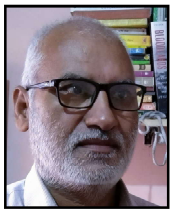

बीते 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद आंकड़ों, परियोजनाओं या चुनावी जीतों में नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में है जो भारत के जनमानस में दिखाई देता है।

– अनिल तिवारी

प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त हुआ है। भारत जैसा विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश किसी नेतृत्व को लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेश दे, यह अपने आप में असाधारण एवं ऐतिहासिक है।

इस कालखंड की सबसे बड़ी विशेषता केवल विकास नहीं, बल्कि विकास और विश्वास का समन्वय है। नेहरू युग को आधुनिक भारत के निर्माण का काल कहा गया, तो वर्तमान युग को उस भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। इस कालखंड में केंद्र की राजग सरकार ने केवल सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीयों के मन में यह विश्वास भी जगाया कि भारत किसी से कम नहीं है और वह विश्व मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है।

इस कालखंड का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री की सबसे विलक्षण विशेषता यह रही कि उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे जनभावनाओं और राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ा। वे उन विरले नेताओं में हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं को केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें जन–आंदोलन का स्वरूप दिया। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सफाई का विषय जो कभी सरकारी विभागों तक सीमित था, उसे राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया।

वर्तमान समय को भारत की गुम होती सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए भी याद किया जाएगा। सदियों से उपेक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों, तीर्थ–स्थलों और सांस्कृतिक विरासत को नई गरिमा मिली। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना के सम्मान का प्रतीक बना। काशी

इन बारह वर्षों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि शासन के केंद्र में पहली बार अंतिम व्यक्ति को रखने का गंभीर प्रयास दिखाई दिया। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया।

विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण और सोमनाथ जैसे तीर्थों का विकास यह संकेत देता है कि आधुनिकता और परंपरा एक–दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकती हैं।

वैश्विक मंच पर भारत आज वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने वाला राष्ट्र बनकर उभरा है। रूस–यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का संकट हो, जी–20 का नेतृत्व हो अथवा वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज उठाने का प्रश्न हो, भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वही भारत है जिसे कभी सपेरों का देश, तो कभी विकासशील देशों की कतार में खड़ा माना जाता था, लेकिन आज दुनिया इसकी आर्थिक प्रगति रफ्तार को आंकते हुए समाधान प्रदाता राष्ट्र के रूप में देख रही है।

इन बारह वर्षों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि शासन के केंद्र में पहली बार अंतिम व्यक्ति को रखने का गंभीर प्रयास दिखाई दिया। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। शासन की पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका सीमित हुई। डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीक को केवल महानगरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव–गांव तक पहुंचाया।

भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि देश में अनाज की कमी न हो और भूख से बचाव हो जाए। आज किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि सिर्फ 'उत्पादन के क्षेत्र' तक सीमित न होकर किसान की समृद्धि, जोखिम, सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बन गई है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियां फसल उत्पादन के बजाय किसान की वास्तविक आय, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती जैसे पहलुओं पर केंद्रित हैं। सरकार ने किसान की जोखिम. सुरक्षा

को भी प्राथमिकता दी है। सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि, अवसंरचना, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज, चेन में निवेश ने उत्पादन, भंडारण और बाजार तक पहुंच को मजबूत किया है।

असमानता को दूर करने के लिए पीएम धन–धान्य कृषि योजना की संकल्पना की गई है। इसके तहत सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, बीज, उर्वरक, फसल विविधीकरण, पशुपालन, बागवानी, कृषि–उपकरण, कौशल विकास, अवसंरचना और बाजार .जुड़ाव जैसी सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हो पा रही हैं। सरकार का इरादा स्पष्ट है कि किसान की आय बढ़े, उसकी मेहनत का उचित सम्मान और मूल्य मिले।

ग्रामीण किसानों की समृद्धि के लिए भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मूर्त रूप दिया है। इसका लक्ष्य किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराना और उनकी बंजर जमीन से अतिरिक्त आय के अवसर निर्मित करना है। इस योजना के तहत किसान अपनी बंजर या कृषि योग्य जमीन पर दो मेगावाट तक के छोटे सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 25 वर्षों तक एक सुनिश्चित आय प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई के लिए डीजल से चलने वाले पंपों को सोलर पंप में बदलने के लिए सरकार 60 प्रतिशत तक का अनुदान देती है। इस योजना के तहत 34422 करोड रुपए की वित्तीय सहायता से मार्च 2026 तक 34800 मेगावाट सौर क्षमता को जोड़ा जा चुका है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि संकल्प बोध के साथ सरकार ने कुछ बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप दिया हैं। चाहे धारा 370 का उन्मूलन हो, तीन तलाक पर रोक हो, जीएसटी लागू करना हो, महिला आरक्षण विधेयक हो अथवा नक्सलवाद और आतंकवाद के विरुद्ध कठोर नीति। इन सभी निर्णयों में राजनीतिक जोखिम था, लेकिन सरकार ने जोखिम उठाने का साहस दिखाया। शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन, सेना में अग्नि वीरों की भर्ती, स्वर्ण जातियों के लिए आरक्षण जैसे फैसले लेना सरकार की दृढ़इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

'स्वदेशी जागरण मंच' स्वावलंबी भारत अभियान के जरिए इसके लिए लगातार प्रयासरत है। मंच का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा और ग्रामीण आबादी है। यदि इस ऊर्जा को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ा गया तो भारत केवल विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है।

हालांकि, किसी भी लोकतांत्रिक शासन की तरह चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ती लागत, सामाजिक विषमताएं तथा आर्थिक अवसरों का असमान वितरण ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान अभी अपेक्षित है। भारत यदि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ चिकित्सा, रोजगार सृजन और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। मोदी सरकार के आगामी वर्षों से सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाए। भारत को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां ईमानदारी अपवाद नहीं, सामान्य व्यवहार बने। शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यावसायिक माफियाओं के प्रभाव से मुक्त कर आम नागरिक की पहुंच में लाया जाए। साथ ही उद्यमिता को बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित रखने के बजाय गांवों, युवाओं और महिलाओं तक पहुंचाना होगा ताकि प्रत्येक नागरिक रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन सके।

'स्वदेशी जागरण मंच' स्वावलंबी भारत अभियान के जरिए इसके लिए लगातार प्रयासरत है। मंच का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा और ग्रामीण आबादी है। यदि इस ऊर्जा को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ा गया तो भारत केवल विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है।

इसी प्रकार महिला शक्ति को विकास की मुख्यधारा में पूर्ण भागीदारी देकर राष्ट्र निर्माण की गति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

कुल मिलाकर बीते 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद आंकड़ों, परियोजनाओं या चुनावी जीतों में नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में है जो भारत के जनमानस में दिखाई देता है। केंद्र सरकार ने बारह वर्षों में विकास की संरचनाएं खड़ी की हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने करोड़ों भारतीयों के भीतर भविष्य के भारत की एक आकांक्षा जगाई है। 2047 के विकसित भारत का संकल्प तभी साकार होगा जब विकास के साथ विश्वास, समृद्धि के साथ समान अवसर और शक्ति के साथ संवेदनशीलता भी जुड़ेगी। परम वैभव के लक्ष्य की ओर बढ़े संतुलित कदमों का यदि यह संतुलन बना रहता है, तो इतिहास इस कालखंड को केवल एक लंबे राजनीतिक कार्यकाल के रूप में नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण युग के रूप में याद करेगा। ❑❑

मोदी युग में डिजिटल बदलाव

भारत गांवों का देश है। तेज रफ्तार शहरीकरण के बावजूद आज भी लगभग 60 प्रतिशत आबादी गांवों से सीधे तौर पर जुड़ी है। आजादी के बाद उम्मीद जगी थी कि भारत के गांवों में भी खुशहाली आएगी, विपन्न किसानों के दिन बहुरेंगे लेकिन तत्कालीन सरकारों की नीति और नीयत के चलते अधिकांश गांव हासिये पर ही रहे। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में राजग सरकार के गठन के बाद शासन में पारदर्शिता लाने और सरकार की योजनाओं में अंतिम व्यक्ति को भी शामिल किए जाने के लिए ई गवर्नेंस मॉडल को प्रमुखता दी गई। देश की ग्राम पंचायतों में डिजिटल बदलाव की रफ्तार तेज हुई।

अब ग्राम पंचायतों में डिजिटल पहुंच बढ़ने के साथ ही विकास की दौड़ में आगे बढ़ने की होड़ है। सरकार भी इसके लिए समर्पित भाव से पंचायतों की डिजिटल जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही है। पंचायत में ऑनलाइन सेवाएं, डेटा आधारित योजनाएं और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली पहलों को पुरस्कृत भी करती है। इस साल पंचायत से जुड़ी चार पहलों सहित कुल 17 उत्कृष्ट डिजिटल परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर 'ई–गवर्नेंस अवार्ड 2026' दिए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र और त्रिपुरा की ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। विकसित भारत 2047 की थीम पर जुलाई माह में जयपुर में आयोजित होने वाले 29 वें नेशनल कांफ्रेंस के दौरान चयनित पंचायतों को सम्मानित करने की घोषणा हुई है।

डिजिटल गवर्नेंस यानी ई–शासन का अर्थ है आईसीटी का उपयोग करके नागरिकों तक सरकारी सेवाओं, सूचनाओं और प्रक्रियाओं को पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाना तथा लालफीताशाही को कम करते हुए शासन प्रणाली में नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

आजादी के बाद देश में गठित पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए योजना आयोग ने अनेक नीतियों का निर्माण किया लेकिन तत्कालीन नेताओं की नीयत में खोट होने के कारण योजनाएं जमीन पर सही–सही नहीं पहुंच सकी। पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी ने एक मौके

इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा उत्साही नेतृत्व के कारण आम भारतीयों की मानसिकता में भी बदलाव आया है। अब भारत समस्या गिनाने वाला नहीं बल्कि समाधान बताने वाला देश बनने की ओर अग्रसर है।

– शिवनंदन लाल

पर स्वीकार किया था कि केंद्र की ओर से एक रुपए की सहायता भेजी जाती है तो 10 से 15 पैसा ही पहुंच पाता है।

वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजग सरकार के गठन के बाद ई शासन के मोर्चे पर काम शुरू हुआ। बीते 12 वर्षों में डिजिटल बदलाव की बहार दूर–दराज के इलाकों में भी सहजता से महसूस की जा रही है।

जन धन योजना, बड़ी कामयाबी

हालांकि, 2014 तक भारत प्रगति के नए सोपान पर खड़ा था। अब संस्थाएं बनाने की चुनौती नहीं थी। बल्कि, बड़ा प्रश्न यह था कि तकनीकी और डिजिटल युग में सिमटती दुनिया में, 1.4 अरब की आबादी के लिए, सटीक और सार्थक नतीजे देने के लिए, मौजूदा संस्थाओं को अधिक जवाबदेह, कुशल और सक्षम कैसे बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की उम्मीदों के अनुरूप शासन व्यवस्था को बदलने में बड़ा योगदान दिया है।

पिछले दशक में भारत ने शासन में नीति निर्माण से जुड़ी ऐसी पहल की हैं, जिनका उदाहरण शायद ही दुनिया में और कहीं दिखाई देता है। करोड़ों नागरिक जो पहले बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, उन्हें जन–धन योजना के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। आज देश में 56 करोड़ से अधिक जन–धन खाते खोले जा चुके हैं, जो विश्व में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा – खाते महिलाओं के हैं। इसके साथ ही, देशभर में स्वच्छता, आवास, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ ईंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं तक नागरिकों की पहुंच बढ़ी है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव

मोदी युग में भारत डिजिटल टेक्नॉलजी का केवल उपभोक्ता रहने के बजाय, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्लोबल इनोवेशन हब बन रहा है। आधार–इनेबल्ड सर्विसेज, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कोविन और अन्य डिजिटल पहल के माध्यम से पता चलता है कि तकनीक का उपयोग केवल सुविधा के लिए ही नहीं, बल्कि सबका साथ–सबका विकास की भावना से आगे बढ़ते हुए, पारदर्शिता और जनहित में भी किया जा सकता है। आज दुनिया भर में भारत के डिजिटल गवर्नेस मॉडल की चर्चा हो रही है।

भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया है। सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, डिजिटल कनेक्टिविटी और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। इनका असर सकल भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अमेरिका रूस चीन ब्रिटेन सहित विश्व के हर हिस्से में भारत को अब एक विकसित देश के नजरिये से देखा जाने लगा है। भारत ने भरोसेमंद आर्थिक पार्टनर, डिजिटल इनोवेशन लीडर, ग्लोबल साउथ की आवाज, क्लाइमेट एक्शन, हेल्थकेयर, सप्लाई चेन, नई टेक्नॉलजी और स्ट्रैटिजिक स्टेबिलिटी पी जैसे मुद्दों पर बातचीत करने वाले देश के तौर पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है।

सुरक्षा नीति में फेरबदल

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की एक और महत्वपूर्ण पहल, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में आया बड़ा बदलाव है। भारत लंबे समय से सीमा–पार आतंकवाद की चुनौती का सामना करता रहा है। विभिन्न सरकारों ने इस चुनौती का सामना किया है। हालांकि, पिछले दशक में आतंकवाद को लेकर आए रणनीतिक बदलाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। एक ऐसा रुख, जिसमें रक्षा तैयारियों, मजबूत सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर, खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन, कूटनीतिक लामबंदी, इसका साफ सदेश है कि आतंकवाद और बातचीत साथ–साथ नहीं चल सकते।

उरी आतंकी हमले के बाद 'लाइन ऑफ कंट्रोल' के पार 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। पुलवामा हमले के बाद 2019 में हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक ने इसे और मजबूत किया। 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती मिलने पर निर्णायक रूप से जवाब देने की उसकी क्षमता को दिखाया है। इसके साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सीमा पर बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश किया जा रहा है।

विकसित भारत

प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो इसका महत्व, केवल उनके कार्यकाल की अवधि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस बदलाव से भी है, जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। 'विकसित भारत 2047' का विजन, ऐसी ही महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जो केवल आर्थिक विकास से कहीं आगे की सोच रखती है। इसमें आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को वैश्विक स्तर पर विकसित, समावेशी, इनोवेटिव और प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प शामिल है।

इस संकल्प को पूरा करने के लिए गांवों की भागीदारी जरूरी है। ई–शासन के माध्यम से हो रहे डिजिटल बदलाव ने प्रगति क्या रास्ता सुलभ किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा उत्साही नेतृत्व के कारण आम भारतीयों की मानसिकता में भी बदलाव आया है। अब भारत समस्या गिनाने वाला नहीं बल्कि समाधान बताने वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। ❑❑

(लेखक आकाशवाणी, दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी हैं।)

आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में स्वदेशीः

आत्मनिर्भरता से रणनीतिक एकीकरण की ओर

ऐतिहासिक रूप से 'स्वदेशी' शब्द चरखा, लाइसेंस–परमिट राज और एक सुसंगत नीतिगत संदेश को जन्म देता रहा है कि भारत को दुनिया को बाहर रखकर निर्माण करना चाहिए। 1950 से 1991 तक आयात–प्रतिस्थापन युग ने ऊंची टैरिफ दीवारों के पीछे घरेलू वस्तुओं का निर्माण करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बजाय अकुशलता, अप्रचलन और तथाकथित 'हिंदू विकास दर' को जन्म दिया। 1991 के बाद के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को खोला, फिर भी भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के नियंत्रक के बजाय मुख्यतः विदेशी वस्तुओं के आयातक उपभोक्ता के रूप में छोड़ दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अधिकतर सेवाओं और सॉफ्टवेयर में प्रवाहित हुआ, जबकि विनिर्माण पिछड़ा रहा।

प्रधानमंत्री मोदी के 2026 के कूटनीतिक दौरे ने एक मौलिक पुनर्विचार का संकेत दिया है। स्वदेशी की पुरानी परिभाषा – आत्मनिर्भरता के माध्यम से आत्म–संयम – चुपचाप समाप्त हो चुकी है। उसके स्थान पर एक नया सिद्धांत खड़ा है, वैश्विक नेटवर्कों के भीतर आत्म–स्वामित्व, जिसमें भारतीय श्रमिक और कंपनियाँ कारखाने के फर्श पर स्वामित्व रखते हुए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, पूंजी और साझेदारियों को आमंत्रित करते हैं।

रणनीतिक तर्कः समझौता ज्ञापन और क्षेत्रीय गहराई

दौरे के दौरान प्राप्त प्रतिबद्धताएँ एक सुसंगत रणनीतिक तर्क को प्रकट करती हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, टाटा समूह ने एएसएमएल (नीदरलैंड) के साथ उन्नत वार्ता की, जिसके पास अत्याधुनिक चिप्स के लिए आवश्यक एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीनों पर लगभग एकाधिकार है। कोई टैरिफ युद्ध एएसएमएल को उस ज्ञान को हस्तांतरित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था; केवल एक रणनीतिक साझेदारी जो बाजार पहुँच, निवेश गारंटी और कूटनीतिक सद्भावना प्रदान करती है, ऐसा कर सकती थी।

स्वदेशी 2.0 रोम में डिप्लोमैटिक सेल्फी पर नहीं जीता जाएगा; यह धोलेरा में वेफर स्टार्ट्स पर जीता जाएगा।

– प्रो. दीपक शर्मा

ग्रीन हाइड्रोजन में, स्वीडन और नॉर्वे ने इलेक्ट्रोलाइज़र प्रौद्योगिकी और कार्बन कैप्चर को कवर करने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत का राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन – 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य – नॉर्डिक विशेषज्ञता के बिना सफल नहीं हो सकता। शुरुआत से सब कुछ आविष्कार करने का प्रयास करने (एक क्लासिक स्वदेशी जाल) के बजाय, सरकार ज्ञान आयात कर रही है और उसे घरेलू विनिर्माण में समाहित कर रही है। इसी तरह, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और रक्षा शिपिंग के लिए यूएई की 5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता भी इसी पैटर्न का अनुसरण करती है, ऊर्जा सुरक्षा, एक मूल स्वदेशी लक्ष्य, विदेशी पूंजी और बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जिसे भारतीय श्रमिक और बंदरगाह संचालित करते हैं।

यदि इस नए मॉडल का कोई भौतिक पता है, तो वह गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही ताइवान की पावरचिप के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण कर रही है। नीदरलैंड का सेमीकंडक्टर समझौता कूटनीतिक आवरण और आपूर्ति शृंखला पहुँच प्रदान करता है, जबकि यूएई– लिंक्ड लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा परियोजनाएँ 3,000 आरक्षित एकड़ पर कब्जा करती हैं। यूरोप प्रौद्योगिकी लाता है; यूएई पूंजी लाता है; धोलेरा भूमि, श्रम और राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदान करता है। यह एक दीवारों वाला बगीचा नहीं है, बल्कि नियंत्रित एकीकरण है।

यदि 40 बिलियन डालर के समझौता ज्ञापनों का 30 प्रतिशत तीन वर्षों में पूंजीगत व्यय के रूप में साकार होता है, तो भारत 12 बिलियन डालर का नया निवेश देख सकता है। वर्तमान पूंजी–से–रोजगार अनुपात पर, इसका तात्पर्य लगभग 480,000 प्रत्यक्ष विनिर्माण नौकरियाँ और उससे दोगुनी अप्रत्यक्ष भूमिकाएँ हैं। अकेले धोलेरा उनमें से 120,000 का दावा कर सकता है, जो संभावित रूप से 22,000 वर्ग किलोमीटर के ब्लूप्रिंट को गुजरात के शेनझेन के जवाब में बदल सकता है।

आलोचनाएँ और रणनीतिक प्रत्युत्तर

घरेलू राजनीतिक प्रवचन में, विदेशी फर्मों को आमंत्रित करना लंबे समय से आत्मनिर्भरता के विश्वासघात के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। आलोचना स्वयं लिखती है– "आप अपने रणनीतिक क्षेत्रों को डच और एमिराती कंपनियों को सौंप रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ?" सरकार का अंतर्निहित उत्तर यह है कि 21वीं सदी की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए अलगाव नहीं, बल्कि गहन एकीकरण की आवश्यकता होती है। चीनी कच्चे माल पर निर्भर एक सेमीकंडक्टर फैब असुरक्षित है; डच मशीनों पर निर्भर लेकिन भारतीय इंजीनियरों द्वारा संचालित और भारतीय कंपनियों के स्वामित्व वाला एक फैब रणनीतिक रूप से स्वायत्त है, भले ही प्रौद्योगिकी कहीं और उत्पन्न होती है। पुराना स्वदेशी सब कुछ बदलना चाहता था। नया स्वदेशी मूल्य शृंखला की सबसे मूल्यवान परतों – असेंबली, परीक्षण, पैकेजिंग और अंततः डिजाइन – का स्वामित्व चाहता है। एएसएमएल मशीनें डच ही रहेंगी, लेकिन धोलेरा में उत्पादित वेफर्स भारतीय होंगे, जैसे नौकरियाँ और निर्यात राजस्व भारतीय होंगे।

कार्यान्वयन की बाधाएँ

सावधानी अभी भी आवश्यक है। 2014 और 2024 के बीच, भारतीय राज्यों ने 1.2 ट्रिलियन डालर से अधिक मूल्य की प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए, लेकिन वास्तविक एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन डालर था – जो हाथ मिलाने और गुनगुनाते कारखाने के फर्श के बीच का अंतर है, जिसने कई महत्वाकांक्षी घोषणाओं को विफल कर दिया है। तीन स्थायी बाधाएँ हैं भू–अधिग्रहण, उपयोगिता बुनियादी ढाँचा और कुशल श्रम। धोलेरा के फैब क्लस्टर को प्रति दिन 50 मिलियन लीटर अल्ट्रा–प्योर पानी और एक गीगावाट स्थिर बिजली की आवश्यकता होती है, दोनों अभी भी निर्माणाधीन हैं। गुजरात के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रतिवर्ष 1.4 लाख स्नातक तैयार करते हैं, लेकिन चिप–विशिष्ट प्रशिक्षण केवल पिछले वर्ष शुरू हुआ। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी जैसे वियतनाम और मैक्सिको बाध्यकारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जबकि भारत अभी भी समझौता ज्ञापन चरण में है। जैसा कि एक यूरोपीय सीईओ ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा– "हमें भारत का लोकतंत्र पसंद है। हमें वियतनाम की गति बहुत पसंद है।"

मोदी का 2026 का दौरा यूरोपीय राजधानियों में भारत को 'बाजार' से 'निर्माता' के रूप में सफलतापूर्वक पुनः ब्रांडेड करने में सफल रहा। 40 बिलियन डालर का आंकड़ा वास्तविक सौदेबाजी के दम को दर्शाता है। हालाँकि, उस दम को कारखाने के फर्श में बदलना निष्पादन पर निर्भर करता है– 900 दिनों में नहीं, बल्कि 90 दिनों में पर्यावरणीय मंजूरी; 2027 तक जल और विद्युत लाइनें जुड़ी हुई; और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पारंपरिक फिटर ट्रेडों के लिए नहीं, बल्कि चिप फैब्स के लिए पुनः तैयार किया जाना। स्वदेशी 2.0 रोम में डिप्लोमैटिक सेल्फी पर नहीं जीता जाएगा; यह धोलेरा में वेफर स्टार्ट्स पर जीता जाएगा। एक पीढ़ी में पहली बार, भारत के पास पुराने प्रश्न – राष्ट्रवादी और वैश्विक दोनों कैसे बना जाए – का एक सुसंगत उत्तर है। उत्तर दीवारें नहीं है; यह कार्यक्षेत्र हैं। ❑❑

डिजिटल व्यसन–वृत्ति

सोशल मीडिया और डिजिटल इकोसिस्टम के दुष्प्रभावों पर लंबे समय से हो रही चर्चा अब घर के अंदर आकर परिवारों के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुकी है और व्यसन–वृत्ति बनकर विशेषकर हमारे युवा वर्ग और छोटे बच्चों के जीवन पर खतरे के रूप में मंडरा रही है। जीवन की निजता अब कोई विकल्प नहीं रह गयी है। इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के प्रयोग के लिए कम से कम इतनी बड़ी क़ीमत चुकाना किसी भी मापदंड से क्षम्य नहीं है। अपने ही परिवारों में एक वर्ष का नवजात शिशु स्मार्टफोन पर नन्ही–सी अंगुली स्क्रॉल करता है और उसके लिए हठ करता है तो दो–तीन वर्ष बाद उसकी यही प्रवृत्ति उसके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधक बनती है। माता–पिता भी अपने छोटे बच्चों को विद्यालय में मोबाइल स्मार्टफोन दे देते हैं और विद्यालय में अध्यापक व्हाट्सएप समूह बनाकर होमवर्क और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां करते हैं तो इस प्रकार से बहुत छोटी आयु से ही माता–पिता–गुरु सब मिलकर इस डिजिटल व्यसन–वृत्ति को परोक्ष अपरोक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। कोरोना काल में स्मार्ट कक्षाओं के नाम पर विद्यार्थियों ने विशेष रूप से इस विशेष रुचि लेना प्रारंभ किया है। जहां शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति ने इसमें विशाल विस्तार किया है, वहीं छात्र कहीं से भी, कैसा भी ज्ञानार्जन बिना रोक–टोक कर रहे हैं भले ही इसकी सत्यता प्रमाणित हो न हो। इस दिशा में गेमिंग प्लेटफार्म बालकों, युवाओं, प्रौढ़ एवं वृद्धों के लिए अपनी निजी सूचना, बैंक खातों आदि को शेयर करना और घंटों तनावपूर्ण रहना उनके मूल्यवान जीवन के क्षरण के कारक हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, एजुकेशनल वैबसाइट और गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से छात्र अपनी निजी जानकारी साझा कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वह किस प्रकार और कहां एकत्रित हो रही है और विज्ञापनों, साइबर ठगी और निजी जीवन में उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है।

बालकों और युवा वर्ग को डिजिटल व्यसन–वृत्ति में धकेलने के लिए वर्तमान में विद्यालयों में उनकी शिक्षा पद्धति जो शिक्षण को डिजिटल माध्यमों पर अतिरेक निर्भरता भी उत्तरदायी है। इसका एक पक्ष यह भी है कि इन शैक्षणिक डिजिटल माध्यमों में शिक्षा और

विकसित देशों में भी डिजिटल व्यसन–वृत्ति के प्रति सजगता बढ़ रही है। सबसे पहले अपने ही परिवार समूहों में कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है तभी इसको आगे ले जा सकेंगे।

– विनोद जौहरी

डाटा प्रोफाइलिंग का भेद मिट रहा है और छात्रों का ज्ञानार्जन सोशल मीडिया के अधीन हो गया है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का उल्लेख आवश्यक है। मुख्य रूप से यह भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता पर जोर देता है। यह कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ताओं का डेटा जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करता है और डेटा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नागरिकों के हाथ में सौंपता है। यह कानून मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट बातों पर जोर देता है। कोई भी कंपनी या संस्थान किसी व्यक्ति की स्पष्ट अनुमति के बिना डेटा एकत्र या उपयोग नहीं कर सकता। नागरिकों को अपने डेटा तक पहुँचने, उसे सही करने, या काम पूरा हो जाने पर उसे हटाने का अधिकार प्राप्त है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा इस्तेमाल करने के लिए माता–पिता की सहमति अनिवार्य है। बच्चों की ट्रैकिंग या लक्षित विज्ञापनों पर सख्त रोक है। कंपनियों को डेटा सुरक्षित रखने के लिए कड़े उपाय करने होंगे और डेटा लीक होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड को तुरंत सूचित करना होगा।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 9 बच्चों और विशेष रूप से अक्षम व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित है। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का डेटा का प्रसंस्करण करने से पहले, डेटा फिड्यूशरी को उनके माता–पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। माता–पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति का यह नियम उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है, जो स्थायी रूप से अक्षम हैं और सहमति देने में असमर्थ हैं। कोई भी डेटा फिड्यूशरी ऐसी किसी भी डेटा प्रोसेसिंग

डिजिटल व्यसन–वृत्ति को दूर करने का दायित्व केवल सरकार का नहीं है। सामाजिक सजगता और जागरूकता को बड़े स्तर प्रचारित करने की आवश्यकता है।

गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता, जिससे बच्चों के कल्याण पर कोई भी प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव पड़े। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्षित करके विज्ञापन या ट्रैकिंग करने पर कठोर प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने या डेटा लीक होने पर कंपनियों पर 50 करोड़ रूपये से लेकर 250 करोड़ रूपये तक का भारी अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। यथार्थ में इन डिजिटल माध्यमों में एप्रूवल देने की प्रक्रिया में सभी वांछित जानकारी बिना किसी सजगता के साझा कर दी जाती है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का अनुपालन और क्रियान्वयन एवं प्रबंधन बहुत कठिन है। परंतु क्या वास्तव में इस अधिनियम का पालन हो रहा है और क्या हम वास्तव में अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हैं?

फूड डिलीवरी के डिजिटल प्लेटफार्म की बाढ़ सी आ गयी है और घर की रसोई का सम्मान और पवित्रता की रक्षा करना कठिन हो रहा है। दिल्ली में औसतन 100 घरों की आवासीय सोसायटियों में दिन भर मे पचास से अधिक फूड डिलीवरी होती है। भोजन किस माध्यम से, कहां, किन पदार्थों से और किस सुरक्षा के अंतर्गत तैयार हो रहा है, इन मानकों का कोई मापदंड नहीं पालन होता और विशेषकर युवा वर्ग में इसके प्रति विशेष आकर्षण है। रात बारह बजे भी फूड डिलीवरी हो रही है। पूरी रात फूड डिलीवरी की भी भरपूर सुविधा उपलब्ध है। इसको लेकर स्वास्थ्य पर कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है, इसका आंकलन भी आवश्यक है।

मनोरंजन के डिजिटल साधनों, ओटीटी, वैब सीरीज, रील्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और टिकटाक जैसे माध्यमों ने परिवारों, छोटी आयु के बालकों और युवा वर्ग पर विपरीत प्रभाव डाला है जिससे उनके व्यक्तित्व पर हठधर्मिता, फोकस की कमी, बैचेनी, क्रोध, स्मरण शक्ति का क्षरण, दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति, हीन भावना, अकेलेपन की प्रवृत्ति आदि साधारण रूप से देखने को मिल रहे हैं और अभिभावक परेशान हैं। छात्रों में शोध, पुस्तकों के प्रति रुचि और उनके संचार कौशल का क्षरण हो रहा है और उनके सामान्य व्यवहार में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के दुरुपयोग ने सत्य और असत्य का भेद समाप्त कर दिया है। 'डीपफेक' इसी का उदाहरण है। यहां तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी है कि न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सावधानी से प्रयोग किया जाये जिससे एआई जेनेरेटेड न्यायिक रेफरेंस की असत्यता पर सजग रहा जाये।

डिजिटल व्यसन–वृत्ति को दूर करने का दायित्व केवल सरकार का नहीं है। सामाजिक सजगता और जागरूकता को बड़े स्तर प्रचारित करने की आवश्यकता है। विद्यालयों में शिक्षा पद्धति में बड़े सुधारों की आवश्यकता है। लचर कानून किसी की रक्षा नहीं करते बल्कि इसके दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं। विकसित देशों में भी डिजिटल व्यसन–वृत्ति के प्रति सजगता बढ़ रही है। सबसे पहले अपने ही परिवार समूहों में कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है तभी इसको आगे ले जा सकेंगे। ❑❑

सोने के आयात को रोकने की कवायद

अमरीका–इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आने और कीमतों में लगातार वृद्धि होने से देश का आयात–निर्यात का असंतुलन पहले से भी ज्यादा विकट हो गया है। ऐसे में भारतीय रूपया तेजी से कमजोर होकर 95 से 97 रूपए प्रति डालर के आसपास चल रहा है और कई विशेषज्ञ तो यह आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि यह 100 रूपए प्रति डालर की सीमा भी लाँघ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से यह भावुक अपील की है कि वे न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोग को कम करें, बल्कि विदेशी मुद्रा बचाने हेतु सोने की खरीद को भी कम करे और जरूरत से ज्यादा विदेश यात्राएं भी न करें। हालांकि सोने के आयात पर समय–समय पर आयात शुल्क बढ़ाने से लेकर मात्रात्मक नियंत्रण लगाने तक, कई अंकुश लगाए जाते रहे हैं, लेकिन शायद यह पहली बार है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने लोगों से सोने की खरीद घटाने के लिए अपील की है।

भारत में लोगों का सोने की खरीद के प्रति आकर्षण कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्षों से देश के लोग आभूषणों के रूप में सोने की भारी खरीद करते रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की अपील से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद प्रधानमंत्री आभूषणों की खरीद पर अंकुश लगाने की अपील कर रहे हैं।

क्या आज सोने की सारी माँग आभूषणों के लिए है?

पिछले लम्बे समय से देश में सोना बड़ी मात्रा में आयात होता रहा है। लेकिन इस संदर्भ में खास बात यह है कि जीडीपी में वृद्धि के साथ–साथ सोने का आयात भी बढ़ता रहा है।

– स्वदेशी संवाद

इस संदर्भ में हमें समझना होगा कि पिछले लगभग दो दशकों से देश में आभूषणों के रूप में सोने की खरीद में भारी कमी आई है, लेकिन फिर भी देश में सोने का अयात लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों को देखना और समझना पड़ेगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में कुल सोने का आयात 150 टन रहा, लेकिन आभूषणों के लिए सोने की माँग सिर्फ़ 66 टन ही थी। पूर्व में विश्व स्तर पर आभूषण के लिए सोने की माँग 50 प्रतिशत से ज्यादा होती थी, लेकिन यह लगातार घटते हुए वर्ष 2025 तक मात्र 31 प्रतिशत ही रह गई। वर्ष 2025 में पहली बार निवेश के लिए सोने की माँग, 2175 टन तक पहुँच गई जो आभूषणों हेतु सोने की माँग से भी ज्यादा थी। यानी कहा जा सकता है की देश और विश्व में सोने की माँग इसलिए नहीं बढ़ रही कि स्वर्ण आभूषणों की माँग बढ़ रही है बल्कि क्योंकि लोग अब सोने को निवेश के रूप में भी रखना चाहते हैं। यही नहीं भारतीय रिजर्व बैंक सहित अधिकांश बड़े देशों के केंद्रीय बैंक भी अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में सोने

का अनुपात बढ़ाते जा रहे हैं। गौरतलब है की सितंबर 2025 से लेकर अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 13.92 प्रतिशत से बढ़कर 16.85 प्रतिशत हो चुका है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना ज़रूरी हो जाता है कि हाल ही में कुछ ऐसे समाचार भी आए कि रिज़र्व बैंक ने अपना काफ़ी सोना बेच दिया है लेकिन 3 जून को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सोने के भंडार 880.52 टन पर बरकरार है।

पिछले लम्बे समय से देश में सोना बड़ी मात्रा में आयात होता रहा है। लेकिन इस संदर्भ में खास बात यह है कि जीडीपी में वृद्धि के साथ–साथ सोने का आयात भी बढ़ता रहा है। 1991 के बाद सोने के आयात की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा बढ़ी है। इसका कारण यह भी रहा कि 1991 से पूर्व सोने के आयात पर भारी नियंत्रण था और न केवल ऊंचे आयात शुल्क लगाए जाते थे, बल्कि सोने के आयात के लिए लाईसेंस की अनिवार्यता भी थी। इसके चलते बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी भी बड़ी मात्रा में होती थी। हालांकि अधिकारिक तौर पर सोने के आयात कम होते थे, लेकिन देश में सोने का उपभोग लगातार ज्यादा बना रहा। 1981 से 1985 के बीच बहुत कम सोने का आयात हुआ, लेकिन 1986 से 1988 के बीच नियमों में ढ़ील दिए जाने के कारण सोने के आधिकारिक आयात में थोड़ी–बहुत वृद्धि हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 10 से 20 टन ही प्रतिवर्ष सोना आयात होता था। इस ढ़ील का लाभ उठाते हुए 1989 से 1991 के बीच सोने का आधिकारिक आयात 10 से 30 टन वार्षिक हो गया, जबकि सोने की कुल आवक (तस्करी समेत) 200 से 300 टन प्रतिवर्ष आंकी गई।

1992 में सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिए आयात स्कीम लागू की और 1993 में बैंकों और नामित एजेंसियों के माध्यम से सोने का आधिकारिक आयात होना शुरू हो गया। इसके चलते तस्करी में भारी गिरावट आई और अब आधिकारिक आयात काफी बड़ी मात्रा में बढ़ गया। 1993 से 1994 के बीच 200 टन सोने का आयात हुआ और 1995 से 1997 के बीच यह 400 से 500 टन तक पहुंच गया। और उसके बाद सोने का आयात सामान्यतः 600 से 900 टन वार्षिक तक रहा, जबकि कई वर्षों में तो यह 1000 टन तक पहुंच गया। बढ़ते आयातों के मद्देनजर 2012–13 तक आते–आते सोने पर आयात नियंत्रण वापिस आए और न केवल आयात शुल्क बढ़ाया गया, बल्कि बैंकों पर सोने के आयात को लेकर कई नियंत्रण लगा दिए गए। आयातकों पर यह शर्त लगाई गई कि अपने कुल सोने के आयात का उन्हें कम से कम 20 प्रतिशत पुनर्निर्यात करना होगा।

कोरोना महामारी के दौरान थोड़े समय के लिए सोने का आयात थमा, लेकिन उसके उपरांत उसमें और ज्यादा तेजी आ गई। 2021 के बाद सोने का आयात तो बढ़ ही रहा था, लेकिन 2024 में आयात शुल्क घटाए जाने के बाद 2025–26 तक यह 72 अरब डालर तक पहुंच गया। हालांकि मात्रा की दृष्टि से 2025–26 में 2024–25 की तुलना में कम सोने का आयात हुआ, लेकिन सोने की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के चलते डालरों में सोने का आयात पिछले साल की तुलना में ज्यादा हो गया।

लीक से हटकर विचार करने की जरूरत

समझा जा सकता है कि सोने के बढ़ते आयातों के चलते आज भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों पर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। परंपरागत स्वर्ण आभूषणों के लिए होने के बजाए अब जहां सोने के आयात ज्यादातर निवेश के लिए होने लगे हैं, इसलिए इस बाबत विचार करना जरूरी है कि लोग निवेश के लिए कुछ अलग प्रकार के उपकरणों का उपभोग करें। पूर्व में भौतिक रूप से ही सोना खरीदे जाने की संभावना होती थी, लेकिन अब उसके काफी विकल्प शुरू हो चुके हैं। ईटीएफ उसमें से एक है। गौरतलब है कि देश में विभिन्न प्रकार के ईटीएफ का कुल पूंजीगत मूल्य 1.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आज जो भी सोने में निवेश करना चाहे, वो ईटीएफ में पैसा लगा सकता है, और सोने में मूल्य वृद्धि का लाभ ले सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 4 मई 2026 को एक नए ट्रेडिंग सेगमेंट के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ईजीआर) की शुरुआत की है। यह भारत के विशाल और परंपरा–आधारित सोने के बाज़ार को आधुनिक बनाने और औपचारिक रूप देने की दिशा में एक अहम कदम है। जहाँ ईटीएफ को स्टॉक मार्केट में केवल रुपए में बेचा या ख़रीदा जा सकता है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को कभी भी भौतिक सोने के रूप में बदला जा सकता है। स्टॉक मार्केट में इस प्रकार के उत्पाद आने के कारण अब भौतिक सोने की ख़रीदी कर निवेश करने के दूसरे विकल्प सामने आ रहे हैं, जिससे सोने के आयात की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो सकती है।

हालांकि भौतिक सोने की ख़रीद के कुछ नए विकल्प बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन अभी यह व्यवस्था शैशव काल में ही है। लीक से हटकर कुछ नए प्रकार की व्यवस्था के निर्माण की ज़रूरत है, ताकि लोग भौतिक सोने की ख़रीद से बचें और उन विकल्पों में निवेश करें, ताकि सोने के मूल्य में वृद्धि का लाभ भी उठाया जा सके, और देश में सोने के आयात पर अंकुश भी लग सके। ❑❑

पुण्यभूमि नागदा, नागदा विप्रकुल और परमेष्ठी राज्य मेवाड़

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने अपनी पुस्तक "पुण्यभूमि नागदा, नागदा विप्रकुल और परमेष्ठी राज्य मेवाड़ (त्रिगुण संदर्भ), प्रथम भाग" (प्रकाशितः 2025, उदयपुर) में मेवाड़ राज्य की दिव्य उत्पत्ति तथा नागदा विप्रकुल की उस महत्वपूर्ण भूमिका का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से मेवाड़ के राजवंशीय गुहिल वंश का संरक्षण एवं संवर्धन हुआ। यह वंश विश्व के सर्वाधिक दीर्घकाल तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक माना जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

यह ग्रंथ मेवाड़ के संस्कृत अभिलेखों, एकलिंग माहात्म्य (नागदा का स्थलपुराण), पुराणिक परंपराओं, राणछोड़ भट्टकृत अमरकाव्यम्, मुहणोत नैणसी री ख्यात, महामहोपाध्याय गौरीशंकर ओझा के महत्वपूर्ण प्रकाशनों, कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, नागदा के बड़वाओं द्वारा संरक्षित राजवंशीय वंशावलियों तथा अन्य ऐतिहासिक परंपराओं जैसे मौलिक स्रोतों पर आधारित है।

इस महत्वपूर्ण शोधग्रंथ के दो प्रमुख योगदान हैं:

1. हिंदू एकता और प्रतिरोध का इतिहासः प्रथम, यह ग्रंथ भारतीय इतिहास के प्रारम्भिक मध्यकालीन तथा मध्यकालीन युग में हिंदू एकता पर आधारित राष्ट्रीय पहचान के उद्भव को रेखांकित करता है। इस प्रकार यह कृति भारत में प्रतिरोध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से हुए आक्रमणों के विरुद्ध संघर्ष के इतिहास को समझना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय इतिहास लेखन में राजनीतिक कारणों से इस पक्ष की अक्सर उपेक्षा की गई है। मध्यकालीन भारत के हिंदू राज्यों की आलोचना प्रायः उनकी कथित असंगठित स्थिति के लिए की जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक स्रोत इसके विपरीत हिंदू नेतृत्व द्वारा एकता स्थापित करने और सामूहिक प्रतिरोध के लिए किए गए गंभीर प्रयासों का उल्लेख करते हैं।

यह कृति मेवाड़ की ऐतिहासिक परंपराओं, नागदा विप्रकुल की भूमिका तथा गुहिल राज्य की सभ्यतागत और सांस्कृतिक आधारभूमि के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

– प्रो. नंदिनी सिन्हा कपूर

लेखक ने मेवाड़ राज्य की दिव्य उत्पत्ति पर विशेष प्रकाश डाला है। परंपरा के अनुसार मेवाड़ राज्य की स्थापना का अधिकार संस्थापक बप्पा रावल को भगवान एकलिंगजी महादेव द्वारा प्रदान किया गया था। गुहिल वंश ने स्वयं को एकलिंगजी का दीवान मानकर शासन किया और असंख्य विदेशी आक्रमणों के बावजूद मेवाड़ ने अपनी अखंड हिंदू पहचान को बनाए रखा। पुस्तक में उल्लेख है कि बप्पा रावल के अनेक पूर्वजों ने अरब आक्रमणों के समय सर्वोच्च बलिदान दिए। यह भी वर्णित है कि आठवीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में अरब शक्तियों ने सीरिया, लेबनान, मकरान तथा सिंध तक विस्तृत क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था।

लेखक के अनुसार बप्पा रावल ने कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड, कर्नाटक के चालुक्यों तथा अनेक अन्य हिंदू राज्यों का सैन्य एवं राजनीतिक सहयोग प्राप्त कर अरब शक्तियों को पूर्वी ईरान तक पीछे धकेल दिया। उन्हें उत्तर–पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रावलपिंडी में एक दुर्ग के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है।

बप्पा रावल के उत्तराधिकारी महाराणाओं ने, एकलिंगजी के आशीर्वाद से, पश्चिम और मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध करने हेतु अनेक हिंदू राज्यों को मेवाड़ के

ध्वज तले संगठित किया। बप्पा रावल के पुत्र रावल खुम्माण के तथा बाद में महाराणा सांगा ने भी विभिन्न हिंदू शासकों को संगठित कर बाबर और उसकी सेना के विरुद्ध संघर्ष किया।

इन सभी राज्यों और उनके राजवंशों ने निःसंदेह भारतीय संप्रभुता तथा उसकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की।

2. नागदा विप्रकुल का योगदानः द्वितीय, यह शोधग्रंथ नागदा विप्रकुल के योगदान तथा मेवाड़ की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव के निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है।

शोधग्रंथ की संरचना

यह शोधग्रंथ चार मुख्य अध्यायों में विभाजित है–

- अध्याय 1 : नागदा ऋषिकुल एवं मेवाड़
- अध्याय 2 : त्रेतायुगीन बैजनाथ महादेव, नागदा ऋषिकुल एवं मेवाड़ राज्य
- अध्याय 3 : परमेष्ठी राज्य : नागदा ऋषिकुलों की दूरदर्शिता
- अध्याय 4 : वंशावली लेखन की अतिशय प्रामाणिकता

ग्रंथ का समापन "विशिष्ट अनुपूरक" के साथ होता है।

पुस्तक के अध्याय में नागदा के ऋषिकुल की भूमिका, नागदा की पौराणिक पृष्ठभूमि तथा रामायण कालीन त्रेतायुगीन बैजनाथ महादेव से उसके संबंधों का विवेचन की गई है। अध्याय में मेवाड़ के राजपरिवार और नागदा विप्रकुल के मध्य विद्यमान अटूट संबंधों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जब बप्पा रावल की माता सती हुईं, तब उन्होंने बालक बप्पा को नागदा विप्रकुल की संरक्षण–व्यवस्था में छोड़ दिया। नागदा विप्रकुल ने ही उनका पालन–पोषण किया और आगे चलकर वही बालक मेवाड़

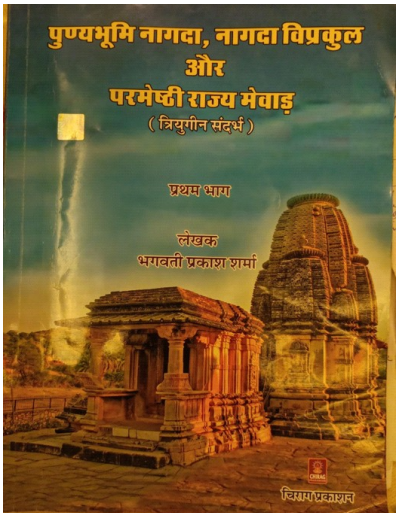

राज्य का संस्थापक शासक बना। लेखक ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख किया है जिसके अनुसार बाल्यावस्था में बप्पा रावल एक ग्वाले के रूप में कार्य करते थे और गुरु हरित की सेवा करते थे। नागदा विप्रकुल द्वारा उनका राजतिलक तथा गुरु हरित द्वारा चित्तौड़गढ़ तक राज्य विस्तार का आशीर्वाद प्राप्त होने का सजीव वर्णन इस अध्याय में मिलता है।

अध्याय में बप्पा रावल के ब्राह्मणीय सांस्कृतिक परिवेश में पालन–पोषण का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये विवरण नागदा विप्रकुल की वंशावलियों में संरक्षित हैं, जिन्हें बड़वाओं द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। लेखक इन वंशावली–पांडुलिपियों को समकालीन अथवा "रीयल टाइम" इतिहास का स्वरूप प्रदान करते हैं।

एकलिंग माहात्म्य में नागदा को एक सर्वोच्च तीर्थ के रूप में स्थापित करने में देवी पार्वती की भूमिका तथा एकलिंगजी महादेव की स्थापना से संबंधित विवरणों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है।

यह भी बताया गया है कि प्राचीन राजा जनमेजय ने ऋषिकुल और मेवाड़ क्षेत्र को 350 गाँव दानस्वरूप प्रदान किए थे।

नागदा विप्रकुल के पूर्वजों को भगवान राम द्वारा बुजड़ा, सिसारमा, पिछोली और आहाड़ नामक चार गाँवों के साथ 52000 बीघा अतिरिक्त भूमि प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसी ऋषिकुल ने उदयपुर जिले की गिरवा तहसील स्थित सिसारमा ग्राम में प्रसिद्ध शैव तीर्थ बैजनाथ मंदिर की स्थापना की।

अध्याय यह स्पष्ट करता है कि गुहिल वंश के उदय से पूर्व भी नागदा विप्रकुल मेवाड़ में अत्यंत प्रभावशाली स्थान रखता था तथा इन ऋषियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है।

यह भी उल्लेखित है कि एकलिंग माहात्म्य की उत्पत्ति पुराणिक परंपराओं से हुई और इसे अंतिम ऐतिहासिक स्वरूप महाराणा कुम्भा के शासनकाल (15वीं शताब्दी ईस्वी) में प्राप्त हुआ।

निस्संदेह, नागदा विप्रकुल ने मेवाड़ के गुहिल राजवंश की स्थापना, संरक्षण तथा "हिंदू सूरज" की अवधारणा को साकार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निष्कर्ष

अपने चारों अध्यायों के आधार पर यह पुस्तक पुण्यभूमि नागदा तथा परमेष्ठी राज्य मेवाड़ से संबंधित ऐतिहासिक परंपराओं और विकासक्रम का व्यापक एवं संगठित विवरण प्रस्तुत करती है। ग्रंथ का समापन "विशिष्ट अनुपूरक" से होता है, जिसमें नागदा विप्रकुल की वंशावलियों को श्री एकलिंगजी से लेकर वर्तमान पीढ़ी तक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें भूमि–अनुदान पत्रों की प्रतिकृतियाँ तथा डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा जी की अन्य प्रकाशित कृतियों की सूची भी दी गई है।

समग्रतः यह कृति मेवाड़ की ऐतिहासिक परंपराओं, नागदा विप्रकुल की भूमिका तथा गुहिल राज्य की सभ्यतागत और सांस्कृतिक आधारभूमि के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ❑❑

सेवा, समरसता और राष्ट्रधर्म की अमर ज्योति

लोकमाता अहिल्याबाई

"जहाँ सत्ता में संवेदना हो, जहाँ धर्म में मानवता हो, जहाँ शासन में लोकमंगल हो–वहीं इतिहास लोकमाता को जन्म देता है।"

भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे युगों तक समाज के लिए प्रेरणा, नैतिकता और लोकसेवा के आदर्श बन जाते हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ऐसा ही एक गौरवशाली नाम हैं। उनकी 301वीं जयंती केवल स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, नारी शक्ति, सामाजिक समरसता और लोककल्याण की उस महान परंपरा को पुनः आत्मसात करने का अवसर है, जिसने भारत की आत्मा को सदियों तक जीवित रखा।

31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गाँव में एक साधारण परिवार में जन्मी अहिल्याबाई बचपन से ही धार्मिक, करुणामयी और कर्मनिष्ठ थीं। सामान्य परिवेश में पली–बढ़ी इस बालिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भविष्य में वह भारतीय इतिहास की सबसे आदर्श शासकों में गिनी जाएँगी। विवाह के बाद वे होल्कर राजघराने में आईं, किंतु उनका व्यक्तित्व केवल राजमहल की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। पति खंडेराव होल्कर और बाद में पुत्र मालेराव की असामयिक मृत्यु ने उनके जीवन को गहरे दुःख में डुबो दिया, परंतु उन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा को लोकसेवा की शक्ति बना दिया।

अहिल्याबाई ने ऐसे समय में शासन की बागडोर संभाली, जब देश का राजनीतिक वातावरण अस्थिरता और संघर्ष से भरा हुआ था। चारों ओर युद्ध, षड्यंत्र और अराजकता थी, किंतु मालवा की धरती पर उनके नेतृत्व में शांति, समृद्धि और न्याय का वातावरण स्थापित हुआ। उन्होंने शासन को अधिकार नहीं, दायित्व माना। उनके लिए राजसत्ता वैभव का साधन नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम थी। वे प्रतिदिन प्रजा की समस्याएँ स्वयं

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर भारतीय इतिहास की अमर ज्योति हैं। उनकी 301वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सेवा, समरसता, न्याय और मानवता के उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे, जिन्हें उन्होंने स्वयं जीकर दिखाया।

– प्रो. रूबी मिश्रा

सुनती थीं और त्वरित न्याय देती थीं। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर-दूर से लोग अपनी समस्याएँ लेकर उनके पास आते थे। उन्होंने कर व्यवस्था को सरल और किसान हितैषी बनाया। किसानों पर अनावश्यक बोझ न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा गया। गरीब, विधवा, असहाय और वंचित वर्गों के प्रति उनकी संवेदना अद्वितीय थी।

अहिल्याबाई भारतीय संस्कृति की उस उदात्त परंपरा की प्रतीक थीं, जिसमें धर्म का अर्थ संकीर्णता नहीं, बल्कि लोकमंगल होता है। वे गहरी आध्यात्मिक आस्था रखती थीं, किंतु उनकी धार्मिकता कभी कट्टरता में परिवर्तित नहीं हुई। उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों के प्रति समान सम्मान का भाव रखा। उनके शासन में योग्यता को जाति और जन्म से ऊपर स्थान मिला। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव को कम करने और विभिन्न वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया।

आज जब समाज अनेक प्रकार के वैचारिक और सामाजिक विभाजनों से जूझ रहा है, तब अहिल्याबाई होल्कर का जीवन सामाजिक समरसता, लोककल्याण और राष्ट्रीय एकता का प्रेरक संदेश देता है। उनका व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति की *"सर्वे भवन्तु सुखिनः"* की भावना का सजीव प्रतीक था, जिसने समाज को समानता, सेवा और सद्भाव का मार्ग दिखाया।

अहिल्याबाई होल्कर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के संरक्षण में माना जाता है। उन्होंने केवल मंदिरों का निर्माण नहीं कराया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, केदारनाथ धाम, गया का विष्णुपद मंदिर सहित अनेक तीर्थस्थलों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार उनके प्रयासों से संभव हुआ। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उन्होंने घाट, कुएँ, बावड़ियाँ, धर्मशालाएँ, सड़कें और विश्राम स्थलों का निर्माण कराया। यह केवल धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने का प्रयास था। उस दौर में जब भारत राजनीतिक रूप से खंडित था, तब अहिल्याबाई ने सांस्कृतिक सूत्रों से देश को जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया।

18वीं शताब्दी का वह दौर महिलाओं के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका सीमित थी, किंतु अहिल्याबाई ने अपनी बुद्धिमत्ता, प्रशासनिक क्षमता और संवेदनशीलता से यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भी सशक्त आधारशिला हो सकती है। उन्होंने कभी अपने दुःख को दुर्बलता नहीं बनने दिया। उनका जीवन आधुनिक भारत की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे सिखाती हैं कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि सेवा, न्याय और संवेदना है।

अहिल्याबाई होल्कर ने अपने शासनकाल में आर्थिक और सामाजिक विकास को समान महत्व दिया। उन्होंने कृषि, व्यापार और जनसुविधाओं के विस्तार हेतु सड़कों, बाजारों तथा संचार व्यवस्था का विकास कराया। जल संरक्षण को उन्होंने लोककल्याण का आधार माना और अनेक कुएँ, बावड़ियाँ तथा तालाब बनवाकर जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया। उनके कुशल प्रशासन के कारण मालवा क्षेत्र आर्थिक समृद्धि और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। आज जब विश्व जल संकट, पर्यावरण असंतुलन और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब अहिल्याबाई का विकास मॉडल संतुलित, पर्यावरण-सम्मत और मानवीय शासन की प्रेरक दृष्टि प्रस्तुत करता है।

वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सांस्कृतिक पुनर्जागरण, विरासत संरक्षण और लोककल्याणकारी योजनाओं को गति मिली है, उसमें कहीं न कहीं अहिल्याबाई की लोकसेवी परंपरा की झलक दिखाई देती है। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान और गरीब कल्याण की योजनाएँ भारतीय सांस्कृतिक चेतना और लोकमंगल की उसी भावना को आगे बढ़ाती प्रतीत होती हैं, जिसकी आधारशिला अहिल्याबाई ने अपने जीवन से रखी थी।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर भारतीय इतिहास की अमर ज्योति हैं। उनकी 301वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सेवा, समरसता, न्याय और मानवता के उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे, जिन्हें उन्होंने स्वयं जीकर दिखाया।

"न सत्ता का अभिमान रहे, न मन में कोई भेद रहे,
जनसेवा ही सच्चा धर्म बने, भारत फिर अहिल्या-सा देश बने।"

अहिल्याबाई का जीवन यह प्रेरणा देता है कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी अपने कर्म, निष्ठा और दृढ़ संकल्प के बल पर समाज और राष्ट्र को नई दिशा दे सकता है। अहिल्याबाई होल्कर ने सेवा, न्याय, लोककल्याण और समरसता के आदर्शों को अपने जीवन में साकार किया। उनका व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति के मानवीय मूल्यों का उज्ज्वल उदाहरण है। यही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा और अमर विरासत है, जो आज भी समाज को मार्गदर्शन प्रदान करती है। ❑❑

विश्व योग दिवस

योगस्य चित्त वृत्ति निरोध

योग केवल शरीर को मोड़ने या कुछ आसान करने का अभ्यास नहीं है। यह आत्मा में छिपे ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करने का मार्ग है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

पूरी दुनिया में 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साह के साथ आयोजित हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत के इस पारंपरिक स्वदेशी ज्ञान को दुनिया न सिर्फ आगे बढ़कर स्वीकार कर रही है, बल्कि इसे अपने जीवन शैली में शामिल कर एक से एक कठिन और असाध्य रोगों से छुटकारा पा रही है, लाभान्वित हो रही है। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक संपूर्ण जीवन–पद्धति है।

12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत में एक बार फिर अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और स्वस्थ जीवन शैली की ताकत का परिचय दुनिया को कराया है। देश में कश्मीर की वीडियो से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तट और मैदान से लेकर लद्दाख की ऊंची चोटियों तक करोड़ों लोगों ने उत्साह के साथ स्वयं भी योग किया और दूसरे को भी योग के लिए प्रोत्साहित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोलकाता में योगाभ्यास किया और योग शिविर में पहुंचे लोगों को भी योग के तरीके और योग से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी साझा की। योग की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग सिर्फ कसरत नहीं है। यह किसी खास उम्र के लिए नहीं है। यह मानवीय भावना की अभिव्यक्ति है। रोज के जीवन में काम, खान–पान और नींद के बीच सही तालमेल तमाम तरह की विपदाओं को खत्म करने का रास्ता है।

भारत के प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों, प्रतियोगिताओं और भौतिक सुखों तक सीमित नहीं। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर छिपी शक्ति, ज्ञान और चेतना को पहचानना है। आज समाज का एक बड़ा वर्ग मानसिक दबाव, असफलता के भय, चिंता और तीव्र प्रतिस्पर्धा से घिरा हुआ है। ऐसे समय में योग और ध्यान जीवन को संतुलित करने की एक महान कला के रूप में सामने आते हैं।

योगस्य चित्तवृत्ति निरोध

योग केवल शरीर को मोड़ने या कुछ आसान करने का अभ्यास नहीं है। यह आत्मा में छिपे ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करने का मार्ग है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है तब वह जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी शांत और दृढ़ होकर कर सकता है। अज्ञान भय आलस और निराशा का अंधकार तभी दूर होता है जब मन संयमित हो, विचार सकारात्मक और लक्ष्य स्पष्ट। योग मनुष्य को यही शक्ति प्रदान करता है।

कहा गया है कि जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तभी भीतर के प्रकाश को खोजने का अवसर मिलता है। अंधकार कभी प्रकाश को पराजित नहीं कर सकता। एक छोटा सा दीपक भी पूरे कमरे को रोशन कर देता है। योग वही दीपक है जो हमारे भीतर ज्ञान संस्कार, आत्मविश्वास और सफलता का प्रकाश जगाता हैं।

भारतीय योग परंपरा में नादयोग ज्ञान को अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली साधन माना गया है। नाद का अर्थ है ध्वनि और योग का अर्थ जुड़ना, यानी नाद योग वह साधन है जिसके माध्यम से साधक अपने भीतर की चेतना से जुड़ने का प्रयास करता है।

भारतीय योग परंपरा में नादयोग ज्ञान को अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली साधन माना गया है। नाद का अर्थ है ध्वनि और योग का अर्थ जुड़ना, यानी नाद योग वह साधन है जिसके माध्यम से साधक अपने भीतर की चेतना से जुड़ने का प्रयास करता है। यह केवल संगीत सुनने या मंत्र जपने की विधि नहीं, आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म ध्वनियों को अनुभव करने की प्रक्रिया है।

आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन्न से निर्मित है। प्रत्येक ग्रह, तारा, जीव और वस्तु अपनी एक विशेष आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। ध्वनि भी ऊर्जा का एक रूप है जो मानव मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। मधुर ध्वनिया मन में शांति और प्रसन्नता उत्पन्न करती है। नाद योग में साधक धीरे–धीरे बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयास करता है। यही अभ्यास मन को स्थिर करता है और चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ❑❑

ऊर्जा सुरक्षा ही नहीं विश्व में भारत की स्थिति मजबूत करती प्रधानमंत्री की यात्राएं

ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राओं के जरिए सीधा लाभ कच्चे तेल की आपूर्ति, वैकल्पिक परिवहन मार्गों की सुरक्षा और हरित ऊर्जा तकनीक तक पहुंच के रूप में प्राप्त होने लगा है, जिससे कि ऊर्जा आपूर्ति स्थिर और सुरक्षित रखने, मंहगाई पर काबू करने तथा विकास की गति को बढ़ाने में मदद मिली है। देश में कच्चे तेल की लगभग 88 प्रतिशत पूर्ति आयात से होती है। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण भारत का तेल आयात बिल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण एक तरफ रूपए में गिरावट हो रही है तो दूसरी तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होता जा रहा है। अमरीका–इजराइल और ईरान युद्ध के प्रथम तीन महीनों में ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 47 अरब डालर कम हो चुका है। इन सब बातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि वे पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग को उतरोत्तर कम करने का प्रयास करें। इस कारण उन्होंने जनता से वर्क फ्राम होम, अधिक सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की भी अपील की है। साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भी उन्होंने सोने की खरीद को कम करने, विदेशी यात्राओं से परहेज करने आदि के लिए भी जनता से गुहार लगाई है।

प्रधानमंत्री की हालिया यात्राएँ कूटनीति और आर्थिक व तकनीकी लक्ष्यों के बीच एक रणनीतिक तालमेल को दर्शाती हैं। ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित करके, निवेश आकर्षित करके, इनोवेशन में साझेदारी को बढ़ावा देकर, और ग्लोबल जुड़ाव को मजबूत करके, भारत खुद को उभरती हुई विश्व व्यवस्था में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर रहा है।
–स्वदेशी संवाद

इन परिस्थितियों में मई 2026 के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली की महत्वपूर्ण यात्राएं आज बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इन यात्राओं का रणनीतिक संदर्भ भी है। लेकिन माना जा रहा है कि इन यात्राओं के पीछे एक बड़ी प्राथमिकता देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग भी है। पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता और वैश्विक तेल बाजारों में उथल–पुथल के चलते यह स्पष्ट है कि भारत इस यात्रा को परंपरागत तेल की आपूर्ति और भविष्य के लिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं को बढ़ाने में सफल हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के तेल आयात का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है, जहां से भारत की कुल कच्चे तेल की आपूर्ति का 11 प्रतिशत प्राप्त होता है। तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में यूएई का तीसरा स्थान है और भारत यूएई की गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। एलपीजी के लिए भी यूएई भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरी तरफ भारत द्वारा परिष्कृत पेट्रोलियम और लुब्रीकेंट का निर्यात भी यूएई में बड़ी मात्रा में होता है और इस संदर्भ में भी उसका दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। भारतीय कंपनियों ने बड़ी मात्रा में यूएई की ऊर्जा परिसंपतियों में निवेश किया हुआ है। यूएई की कंपनी 'मसदर' ने राजस्थान में 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण के लिए समझौता किया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की यात्राओं में यूएई की यात्रा प्रारंभ में शामिल नहीं थी, और अंतिम समय पर 15 मई के लिए यूएई की यात्रा को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जोड़ा गया। यात्रा क्रम में इस बदलाव को कूटनीतिक और आर्थिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे खास यह रही कि आपातकाल में भारत के पेट्रोलियम भंडार की आवश्यकता पूर्ण करेगा और ऐसी किसी भी स्थिति में भारत को गारंटी के साथ तेल की आपूर्ति की जा सकेगी। हालांकि भारत के पास तेल के भंडारण की काफी क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद भी युद्धकाल में ऐसा देखा गया कि यह क्षमता युद्ध की स्थिति में अपर्याप्त है। अबूधाबी नेशनल आयल कंपनी और इंडियन आयल लिमिटेड के बीच एक सहयोग समझौता हुआ, जिससे भारत की एलपीजी आपूर्ति

सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यूएई की यात्रा में खास बात रणनीतिक प्रतिरक्षा साझेदारी का फ्रेमवर्क भी शामिल है। इसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच प्रतिरक्षा और प्रौद्योगिक सहयोग को मजबूत किया जाएगा। जलपोत मरम्मत हेतु गुजरात में एक कलस्टर भी बनाया जाएगा। यूएई द्वारा भारत में निवेश के संदर्भ में भी समझौते हुए। कुल मिलाकर भारत और यूएई के बीच आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय इसके साथ शुरू हो गया है।

यह सही है कि चाहे लंबे समय से देश की अधिकांश ऊर्जा की आवश्यकतायें आयातित पेट्रोलियम पदार्थों से पूरी होती रही हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि देश ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में भी काफी प्रगति की है। आज देश में जितनी बिजली उत्पादन की क्षमता है, उसका 51 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली योजनाओं, न्यूक्लियर ऊर्जा आदि से आता है। इसमें देश लगातार प्रगति कर रहा है, और नवकरणीय ऊर्जा क्षमता जो वर्तमान में 288 गीगावाट है, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य है। इससे न केवल भारत ऊर्जा की दृष्टि से केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि ऊर्जा की आवश्यकताएं जो अभी तक पेट्रोलियम पदार्थों से पूर्ण होती है, अब नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ण हो सकेंगी। पिछले कुछ वर्षों में बैटरी चलित वाहन जैसे ई–रिक्शा, कारें, छोटे और बड़े ट्रक, बस आदि में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। एक तरफ नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि और दूसरी ओर विद्युत चलित वाहनों में प्रगति देश को ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

लेकिन अल्पकाल में देश ऊर्जा की दृष्टि से पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। पिछले लगभग चार माह से चल रहे युद्ध के चलते देश के समक्ष एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, जिससे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बाधित आपूर्ति आदि के कारण देश में महंगाई बढ़ने लगी। इसलिए दीर्घकाल के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, वे अल्पकाल के लिए शायद काफी नहीं है। देश में आने वाले कुछ समय तक पेट्रोलियम पदार्थों की भी कमी को भी दूर करना जरूरी है। गत सप्ताह प्रधानमंत्री द्वारा की गई खाड़ी देशों की यात्राएं इस संदर्भ में अहम मानी जा रही हैं।

प्रधानमंत्री की यात्राओं को देश के समक्ष खड़ी समस्याओं के संदर्भ में देखना होगा।

वैश्विक मानचित्र भारत की मजबूत होती स्थिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की विदेश यात्राएँ, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, नॉर्वे, इटली और अन्य रणनीतिक साझेदार देशों की यात्राएँ, एक तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के एक सोचे–समझे प्रयास को दर्शाती हैं। ये यात्राएँ केवल औपचारिक नहीं हैंय वे भारत की आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा जरूरतों, तकनीकी प्रगति और भू–राजनीतिक प्रभाव से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

इन यात्राओं से ऊर्जा साझेदारियों को मजबूती तो मिली ही, दीर्घकालिक समझौते और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों में सहयोग से भारत को वैश्विक कीमतों में अचानक होने वाले उतार–चढ़ाव और आपूर्ति में रुकावटों में भी राहत मिलेगी। यह विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे भू–राजनीतिक तनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसी तरह, स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश नॉर्वे के साथ जुड़ाव, अपतटीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ शिपिंग के क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोलता है।

द्विपक्षीय लाभों से परे, ये यात्राएँ भारत के बहुपक्षीय जुड़ाव को भी मजबूत करती हैं। उदाहरण के लिए, नॉर्वे वैश्विक जलवायु चर्चाओं और महासागर शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे देशों के साथ संबंधों को गहरा करके, भारत स्थिरता, जलवायु वित्त और 'ब्लू इकोनॉमी' (समुद्री उत्पादों से संबद्ध आर्थिकी) पहलों पर वैश्विक मानदंडों को आकार देने में अपनी आवाज को और अधिक प्रभावी बनाता है।

इन राजनयिक प्रयासों का एक प्रमुख आयाम एक तकनीकी शक्ति के रूप में भारत का उभरना है। पिछले एक दशक में, भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, फिनटेक और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 'डिजिटल इंडिया', यूपीआई जैसी पहलें, और सेमीकंडक्टर तथा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पारिस्थितिकी तंत्र में हुई प्रगति ने भारत को एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार के रूप में स्थापित किया है। इन यात्राओं के दौरान, भारत न केवल निवेश की तलाश कर रहा है, बल्कि अपनी क्षमताओं की पेशकश भी कर रहा है, चाहे वह डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष सहयोग में, या विकासशील देशों के लिए किफायती तकनीकी समाधान प्रदान करने में।

प्रधानमंत्री की हालिया यात्राएँ कूटनीति और आर्थिक व तकनीकी लक्ष्यों के बीच एक रणनीतिक तालमेल को दर्शाती हैं। ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित करके, निवेश आकर्षित करके, इनोवेशन में साझेदारी को बढ़ावा देकर, और ग्लोबल जुड़ाव को मजबूत करके, भारत खुद को उभरती हुई विश्व व्यवस्था में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर रहा है। बढ़ती आर्थिक ताकत वाला एक तकनीकी शक्ति के रूप में, भारत अब ग्लोबल घटनाक्रमों पर सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है, बल्कि उन्हें आकार भी दे रहा है। ❑❑

शिक्षा के मंदिर में 'कोचिंग वॉर' और दांव पर लगता मासूम छात्रों का भविष्य

बिहार के पटना का मुसल्लहपुर हाट इलाका देश भर में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की उम्मीदों का केंद्र माना जाता है। लेकिन हाल ही में इस इलाके से जो तस्वीरें और खबरें सामने आईं, उसने न केवल शिक्षा के इस मंदिर को शर्मसार किया है बल्कि बिहार की गौरवशाली ज्ञान परंपरा पर भी एक गहरा धब्बा लगा दिया है। जिन गलियों में सुबह से शाम तक किताबों के बंडल, पेन और कॉपियां दिखाई देती थीं, वहां अचानक पत्थरबाजी, लाठी–डंडे और हवाई फायरिंग की गूंज सुनाई देने लगी। इस तथाकथित 'कोचिंग वॉर' ने यह साबित कर दिया है कि जब शिक्षा व्यवसाय बन जाती है, तो नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पतन किस कदर होता है।

इस पूरे बवाल की शुरुआत बेहद मामूली और बचकानी वजह से हुई, जिसे जानकर किसी भी सभ्य समाज का सिर झुक जाएगा। बताया जा रहा है कि एक कोचिंग संस्थान की ओर से बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में करीब 12 हजार छात्रों के सफल होने का दावा करते हुए बड़े–बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। आरोप है कि यह पोस्टर प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के साइन बोर्ड के ऊपर या उसके बेहद करीब चिपका दिए गए। इसके बाद वर्चस्व की इस जंग में सीढ़ियां लगाकर बैनर फाड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। पोस्टर फाड़े जाने की इस छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते एक ऐसी आग का रूप ले लिया, जिसने पूरे इलाके के सुरक्षा तंत्र और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दो पक्षों के समर्थक आमने–सामने आ गए, लाठियां चलीं, ईंट–पत्थरों की बौछार हुई और देखते ही देखते वह परिसर कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया।

घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया के महारथी और लाखों युवाओं के आदर्श बने शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर ने मीडिया के सामने आकर बेहद सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कैमरे के सामने पूरी गंभीरता से कहा कि उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है और उन्होंने अपनी आंखों से एक–दो नहीं बल्कि आठ से दस राउंड फायरिंग होते हुए देखी है। एक शिक्षक के मुंह से इस तरह की बात सुनकर पूरे राज्य के अभिभावकों और छात्रों में दहशत फैल गई। लेकिन जब कानून के रक्षकों ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और घटनास्थल के साथ–साथ आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, तो कहानी पूरी तरह पलट गई। पुलिस की शुरुआती जांच में दूर–दूर तक गोली चलने या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा फायरिंग करने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके उलट, सीसीटीवी में यह साफ दिखाई दिया कि खान सर के अपने ही सुरक्षा गार्ड हवा में हथियार लहराते और हमला करते नजर आ रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया और खुद खान सर को भी देर रात लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा।

हैरानी की बात यह है कि जो शिक्षक रात में अपनी आंखों से गोलियां बरसने की गवाही दे रहे थे, सुबह होते–होते उनके सुर पूरी तरह बदल गए। वे अपने ही दावों से यू–टर्न लेते हुए यह कहने लगे कि अब पुलिस की जांच के बाद ही असलियत का पता चलेगा या

सरकार और प्रशासन को अब बिना किसी दबाव के इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी, जो मिसाल बन सके, ताकि बिहार का कोई और होनहार छात्र इस गंदे व्यावसायिक खेल की बलि न चढ़े।

– अजय कुमार

फिर जब उनका घायल गार्ड ठीक होकर आएगा तब वह सच बताएगा। एक शिक्षक के बयानों में ऐसा विरोधाभास और तथ्यों को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही बेहद चिंताजनक है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कभी कहा था कि 'शिक्षक वह नहीं है जो केवल दिमाग में तथ्य ठूंसे, बल्कि वह है जो छात्र को सत्य की खोज के लिए तैयार करे।' लेकिन आज के डिजिटल युग के इन तथाकथित 'गुरुओं' के तथ्य और सत्य दोनों ही गंभीर संदेह के घेरे में आ गए हैं।

इस विवाद का दूसरा पहलू और भी भयावह है। फैजल खान की शिकायत पर पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को फौरन गिरफ्तार कर लिया। रौशन आनंद बिहार के एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद पटना की सड़कों पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया। रौशन आनंद के समर्थन में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का आरोप है कि खान सर ने राजनीतिक और व्यावसायिक रंजिश के तहत उनके गुरु पर झूठे आरोप लगाए हैं। सोचिए, जिन नौजवानों को इस वक्त कमरों में बंद होकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वे अपने–अपने पसंदीदा शिक्षकों के अंधविश्वास में सड़कों पर नारेबाज़ी कर रहे हैं और कानून को हाथ में लेने पर आमादा हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज के ये मशहूर यूट्यूब शिक्षक बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के बजाय अपने निजी स्वार्थ के लिए एक 'ट्रोल आर्मी' और हिंसक भीड़ में तब्दील कर रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है जब पटना की धरती पर कोचिंग संचालकों के कारण इस तरह का उपद्रव हुआ हो। इतिहास गवाह है कि साल 2019 में भी इसी मुसल्लहपुर इलाके में वर्चस्व को लेकर बमबाजी की घटना हुई थी। उस वक्त भी दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण इन दुकानदारों के हौसले बुलंद रहे। इस साल भी सरस्वती पूजा के मौके पर इसी तरह के हिंसक टकराव की खबरें आई थीं। अगर समय रहते पुलिस और प्रशासन ने इन व्यावसायिक संस्थानों पर नकेल कसी होती, तो आज यह नौबत नहीं आती। सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटरों में इसलिए मोटी फीस देकर भेजते हैं कि वे वहां से लहूलुहान होकर लौटें? अगर यह पत्थरबाजी दिन के वक्त होती, जब हजारों छात्र क्लास में मौजूद होते हैं, और किसी मासूम के सिर पर वह पत्थर लग जाता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या ये शिक्षक अपनी अकूत संपत्ति और टीआरपी के नशे में किसी बच्चे की जान की कीमत चुका पाते?

इस पूरे खेल का सबसे कड़वा सच आर्थिक हितों का टकराव है। अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि कुछ शिक्षक बहुत कम पैसे में समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों संस्थानों के फीस स्ट्रक्चर की तुलना की जाती है, तो असलियत कुछ और ही निकलती है। जहां दो साल के ऑफलाइन कोर्स के लिए एक संस्थान किस्तों में दस हजार रुपये लेता है, वहीं दूसरा संस्थान एकमुश्त बीस हजार रुपये वसूलता है। ऑनलाइन कोर्सेस में भी फीस का अंतर जमीन–आसमान का है। जाहिर है, यह पूरी लड़ाई किसी शिक्षा सुधार या गरीब बच्चों के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि यह अधिक से अधिक छात्रों को अपनी ओर खींचने और करोड़ों रुपये का टर्नओवर खड़ा करने की कॉरपोरेट जंग है।

अब इस मामले में पटना पुलिस ने कदमकुआं थाने में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भ्रामक जानकारी फैलाने की संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के बाद खान के सुर बदल गये है। वे कानून का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अतीत में रेलवे परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा और नीट पेपर लीक मामले में एनकाउंटर जैसे उत्तेजक बयान देकर माहौल खराब करते रहे है।

जब कोई मुख्यधारा का माध्यम इन कोचिंग संस्थानों की इस खतरनाक कार्यप्रणाली और उनके गिरते स्तर पर सवाल उठाता है, तो ये यूट्यूब शिक्षक अपने लाखों फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके डिजिटल लिंचिंग शुरू कर देते हैं। जबकि वे खुद यह भूल जाते हैं कि वे शिक्षा के नाम पर कौन सा अनैतिक धंधा चला रहे हैं। सरकार और प्रशासन को अब बिना किसी दबाव के इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी, जो मिसाल बन सके, ताकि बिहार का कोई और होनहार छात्र इस गंदे व्यावसायिक खेल की बलि न चढ़े। ❑❑

बालासाहब देवरसः समाज एवं देशसेवा को समर्पित

बालासाहब देवरस का "बाला साहब" नाम उन्हें उनके परिवार और करीबी लोगों द्वारा प्यार से दिया गया एक उपनाम था, जो उनके वास्तविक नाम मधुकर दत्तात्रेय देवरस के साथ जुड़ या। बाला साहब एक लोकप्रिय मराठी शब्द है जिसका उपयोग छोटे लड़कों या प्रियजनों के लिए किया जाता है। यह उनके मिलनसार और स्नेही स्वभाव को दर्शाता है। 11 दिसम्बर 1915 को नागपुर में जन्मे बाला साहब देवरस पार्वती बाई– कृष्णराव देवरस की आठवीं संतान थे। 1925 में बालसाहेब ने शाखा जाना प्रारम्भ कर दिया। स्थायी रूप से उनका परिवार मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के आमगांव के निकटवर्ती ग्राम कारंजा का था। अभीष्ट, बाला साहब की स्मृतियां, सेवा और आयाम से प्रतिबद्ध पावन भूमि में बाल–भाऊ देवरस न्यास संचालित है। न्यास आर्थिक विकास, खेती प्रचार व प्रशिक्षण, महिला बचत गट प्रशिक्षण केंद्र, फलोद्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम, दुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अरोग्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन जनकल्याण के निहितार्थ करता है।

अनुपम सरस्वती शिशु मंदिर

उनकी सम्पूर्ण शिक्षा नागपुर में ही हुई। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा न्यू इंगलिश स्कूल में हुई। संस्कृत और दर्शनशास्त्र विषय लेकर मौरिस कालेज से बालसाहेब ने 1935 में बीए किया। दो वर्ष बाद उन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। विधि स्नातक बनने के बाद बालसाहेब ने दो वर्ष तक अनाथ विद्यार्थी बस्ती गृह मे अध्यापन कार्य किया। इसके बाद उन्हें नागपुर मे नगर कार्यवाह का दायित्व सौंपा गया। 1965 में उन्हें सरकार्यवाह का दायित्व सौंपा गया जो 6 जून 1973 तक उनके पास रहा। श्री गुरूजी के स्वर्गवास के बाद

बालासाहब के 1973 में संघ के तीसरे सर संघचालक बनने के बाद कुछ लोग उनका चित्र भी लगाने लगे पर उन्होंने इसे रोक दिया। यह उनकी प्रसिद्धि से दूर रहने की वृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है।
– हेमेन्द्र क्षीरसागर

6 जून 1973 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सर संघचालक के दायित्व को ग्रहण किया। उनके कार्यकाल में संघ कार्य को नई दिशा मिली। उन्होंने सेवाकार्य पर बल दिया परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वाचल सहित देश के वनवासी क्षेत्रों के हजारों की संख्या में सेवाकार्य आरम्भ हुए। बालासाहब देवरस ने अपना जीवन समाज एवं देशसेवा को समर्पित कर दिया था। शिक्षा क्षेत्र में सबसे अग्रणी सरस्वती शिशु मंदिर योजना बालासाहब देवरस की ही अनुपम देन है।

प्रसिद्धि से दूरी की वृत्ति

समर्पित, डाक्टर जी का स्वास्थ्य अधिक खराब होने के चलते बालासाहब को 1940 में कलकत्ता से वापस बुला लिया गया। देशभर के विभिन्न स्थानों पर प्रचारक भेजने की जिम्मेदारी नागपुर शाखा की ही सर्वाधिक रहती थी। स्वयंसेवक को उस हेतु गढ़ना, किसे कहाँ भेजना यह जिम्मेदारी बाला साहब उत्तम रीति से संभालते थे। डाक्टर जी के निर्देश पर 1937 से 1940 के बीच गुरूजी संघ कार्य में पूरी तरह डूब गए थे। शाखा पर होने वाले गणगीत, प्रश्नोत्तर आदि की उन्होंने ही शुरुआत की। संघ के कार्यक्रमों में मां भारती, डां हेडगेवार तथा श्री गुरुजी के चित्र लगते हैं। बालासाहब के 1973 में संघ के तीसरे सर संघचालक बनने के बाद कुछ लोग उनका चित्र भी लगाने लगे पर उन्होंने इसे रोक दिया। यह उनकी प्रसिद्धि से दूर रहने की वृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है।

संघ कार्य में नये आयाम

साहसं, 1975 में संघ पर लगे प्रतिबन्ध का सामना उन्होंने धैर्य से किया। वे आपातकाल के पूरे समय पुणे की जेल में रहे; पर सत्याग्रह और फिर चुनाव के माध्यम से देश को इन्दिरा गांधी की तानाशाही से मुक्त कराने की इस चुनौती में संघ सफल हुआ। मधुमेह रोग के बावजूद 1994 तक उन्होंने यह दायित्व निभाया। इस दौरान उन्होंने संघ कार्य में अनेक नये आयाम जोड़े। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्धन बस्तियों में चलने वाले सेवा के कार्य हैं। इससे वहाँ चल रही धर्मान्तरण की प्रक्रिया पर रोक लगी। स्वयंसेवकों द्वारा प्रान्तीय स्तर पर अनेक संगठनों की स्थापना की गई। बालासाहब ने वरिष्ठ प्रचारक देकर उन सबको अखिल भारतीय रूप दे दिया। स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 1994 में सर संघचालक का दायित्व त्याग दिया था। अपूरणीय, बाला साहब देवरस का 17 जून 1996 को स्वर्गारोहण हुआ। प्रथम और द्वितीय सर संघचालकों का दाहसंस्कार स्वयंसेवकों ने नागपुर के रेशमबाग संघ कार्यालय में किया था।

बालासाहब ने स्पष्ट कहा था कि उनका अंतिम संस्कार सामान्य व्यक्ति की भांति श्मशान में किया जाए और उनकी समाधि न बनाई जाए। उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र शब्दांजलि! साभार जीवन प्रसंग! ❑❑

हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

शिक्षित समाज हेतु शिक्षित व्यापारियों को आगे आना होगाः कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि शिक्षित समाज बनाने के लिए शिक्षित व्यापारियों को आगे आना होगा। वे टीम कैट, नागपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापारी संस्कारयुक्त और सज्जन होते हैं। सामाजिक संपर्क के कारण उन्हें व्यापक अनुभव और सामाजिक ज्ञान रहता है। इसी कारण समाज को शिक्षित करने में उनकी भूमिका अहम है।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यापार के विस्तार से पारंपरिक दुकानदारों के सामने चुनौती है। व्यापारियों को नई योजनाओं से ग्राहक आकर्षित करने होंगे। हर वस्तु के संगठन हैं, लेकिन सभी को एक मंच पर आवाज उठानी चाहिए। इसी उद्देश्य से स्वदेशी व्यापारी मंच बनाया गया है।

श्री कश्मीरी लाल ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी व्यापारी मंच बनाया गया है। इसके राष्ट्रीय संयोजक बालकृष्ण भारतीय हैं। नागपुर में भी इस मंच का कार्यालय रहेगा।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक अजय पत्की ने कहा कि इस मंच का नारा है – राष्ट्रहित, व्यापार हित और व्यापारी हित। देशभर में इसकी शाखाएं होंगी। ऊर्जा, ईंधन, सोना, खाद्य तेल जैसी आयातित वस्तुओं की खपत रोकना जरूरी है।

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण भारतीय ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर कब्जे के लिए शीत युद्ध चल रहा है। हर नागरिक, दुकानदार और उपभोक्ता देश का सिपाही है। भाषा, भेष, भूषा, भोजन, भ्रमण में पूर्ण स्वदेशी समय की मांग है। किशोर धाराशिवकर ने कहा कि देश बदलने के लिए स्वयं को बदलना होगा। ध्यानेश्वर रक्षक ने बताया कि सभी संतों ने स्वदेशी का पालन और प्रचार किया।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से स्वदेशी संकल्प लिया। श्री कश्मीरी लाल के हाथों स्वदेशी व्यापारी मंच का उद्घाटन हुआ। आभार राजू जैन ने व्यक्त किया।

इस अवसर पर टीम नागपुर के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, नाग विदर्भ चैम्बर के उपाध्यक्ष सचिन पुनियानी, विनय जैन, दीपा पचौरी, अश्वनी गुप्ता, राजेश लोंदे, पूजा झाम, सरिता चौरसिया, विजय चौरसिया, विनोद गुप्ता, शिवाजी भालतिलक सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

स्वदेशी जागरण मंच ने अमरीकी राजदूत को लिखा पत्र

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने अमरीकी राजदूत को पत्र लिखकर 8 से 11 जून के बीच अमरीका द्वारा किये गये अलग–अलग हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत को लेकर विरोध जताया। मंच ने इस मामले की एक पारदर्शी जांच और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है।

मंच ने अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को लिखे एक पत्र में अमरीकी सशस्त्र बलों द्वारा तीन निहत्थे भारतीय नाविकों की कथित तौर पर बिना किसी उकसावे के हत्या पर 'गहरा दुख और पीड़ा' जतायी है।

मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने पत्र में कहा, "इन घटनाओं ने भारत के लोगों के बीच गहरा आक्रोश और अविश्वास उत्पन्न कर दिया है। अमेरिका प्रशासन की असंवेदनशील और गैर–जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे भारतीय भावनाओं को और ठेस पहुंची है, क्योंकि भारतीयों ने अमरीका को हमेशा एक घनिष्ठ मित्र के रूप में देखा है।"

मंच ने इन घटनाओं की एक पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की, फिर चाहे वे व्यक्ति हों या शासन से जुड़े लोग। संगठन ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे और न्याय की भी मांग की। पत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस आश्वासन और अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के पालन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

महाजन ने कहा, "भारत की पीड़ा गहरी है और उसका संकल्प अडिग है कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और भारतीय नाविकों की गरिमा व सुरक्षा को हर कीमत पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने का अधिकार रखता है। महाजन ने आरोप लगाया कि अमेरिका की यह कार्रवाई समुद्र, सशस्त्र संघर्ष और मानवाधिकारों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है।

https://hindi.theprint.in/india/sjm-writes-to-seek-investigation-and-compensation-for-deaths-of-indian-sailors-in-us-attack/986826/

प्रांतीय कार्यशाला में स्थानीय उद्यमिता और स्वदेशी पर जोर

स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में प्रांतीय विचार वर्ग एवं कार्यशाला का शुभारंभ अंबिकापुर (बिलासपुर) में हुआ। जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल, अर्थशास्त्री एवं स्वदेशी चिंतक प्रो. अश्वनी महाजन, विधायक मान प्रबोध मिंज, स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक सुधीर दाते तथा प्रांत संयोजक एवं स्वावलंबी भारत अभियान के समन्वयक जगदीश पटेल मंचासीन रहे।

स्वागत उद्‌बोधन में जगदीश पटेल ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी चिंतन और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

मुख्य वक्ता प्रो. अश्वनी महाजन ने स्वदेशी आधारित विकास मॉडल, स्थानीय उत्पादन, नवाचार और कौशल विकास को विकसित भारत की आधारशिला बताया। इस अवसर पर दिनेश पाटिल, सुब्रत चाकी, दिग्विजय भाकरे, उमेश पासवान, संजय चौवे, सुमन मुथा, शंकर त्रिपाठी, राजकिशोर चौधरी, उपेन्द्र यादव, किरण सिंह, ठाकुर राम राजवाड़े, योगेश विश्वकर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

स्वदेशी मजबूरी नहीं मजबूती का आधारः सतीश कुमार

हार्मुज जलडमरूमध्य में भड़कती हुई राजनीतिक आग जब पूरी दुनियां की उर्जा आपूर्ति श्रृंखला को हिला रही है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्जा संकट की विकट परिस्थितियां निर्मित कर रही है तब देश के आम नागरिकों की जीवन शैली में स्वदेशी भावना का अभ्युदय मजबूरी का नहीं मजबूती का सशक्त आधार बनकर उभरता है। उक्त विचार अखिल भारतीय

सह संगठक श्री सतीश कुमार ने व्यक्त किए। उन्होंने दैनिक जीवन–चर्या में कुल पांच बिंदुओं पर अपनी आदतों को बदलकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान करने के लिए सोने के क्रय पर नियंत्रण, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा स्वदेशी को प्राथमिकता, मितव्ययिता, तथा उर्जा पानी और अन्य राष्ट्रीय संसाधनों का संयमित तथा विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की। उन्होंने आम नागरिकों उपस्थित जन समुदाय, गणमान्य नागरिकों तथा प्रबुद्ध नागरिकों से समाज को जागृत तथा प्रेरित करने का आह्‌वान किया।

मध्य प्रांत के 16 जिले के उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों ने हरदा में आयोजित प्रांतीय वर्ग की व्यवस्थाओं की भूरि भूरि प्रशंसा की। आयोजन को प्रबंधक रविलाल पटेल, नरेंद्र राठी विनेश पटेल, ओम पटेल, बनवारीलाल यादव, वल्लभ तोषनीवाल, नरेंद्र भांबू सहित संपूर्ण समिति ने पूर्ण लगन, एवं उत्साह से प्रशिक्षण को सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में आभार डा. एल.एन. पाराशर सह प्रबंधक के द्वारा व्यक्त किया गया।

'निर्यातक बनें व्यापारी, तभी देश फिर बनेगा सोने की चिड़िया'

देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ देश के उद्यमी और व्यापारी पर है। इसके लिए हमें सिर्फ आयातक (इम्पोर्टर) बनकर नही रहना है, बल्कि निर्यातक (एक्सपोर्टर) बनने को प्राथमिकता देनी होगी। उक्त बातें स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंगठक श्री सतीश कुमार ने कही। वह अवध जिमखाना क्लब में आयोजित स्वदेशी व्यापारी मंच की प्रथम परिचय बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे।

बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने की। स्वदेशी व्यापारी मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक संदीप बंसल ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि इस मंच के जरिए उद्योग और व्यापार जगत की सभी व्यावहारिक बाधाओं को दूर कराया जाएगा।

बैठक की शुरुआत श्री सतीश कुमार, श्री संदीप बंसल, बीबीएयू के कुलपति डॉ. राजकुमार मित्तल, डॉ. रामकुमार तिवारी और सुरेश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया।

तेल एवं गैस पर निर्भरता कम कर देश को समृद्ध बनाएंः सतीश कुमार

"देश में डीजल पेट्रोल कुकिंग गैस की 88 प्रतिशत निर्भरता दूसरे देशों पर हैं। दूसरे देश पर निर्भर रहकर हम प्रतिदिन चार हजार करोड़ रूपया दूसरे देशों को भेजते हैं। 42 देशों को हम अपना पैसा देते हैं। 55 प्रतिशत एलपीजी का आयात करते हैं। हम बिजली में आत्मनिर्भर हैं दूसरे देशों को हम बिजली निर्यात करते हैं। हम स्वदेशी बिजली से अपनी रसोई में इंडक्शन आदि का प्रयोग कर ऊर्जा बचाने में सहयोग कर सकते हैं और देश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं"।

उक्त विचार जेके पब्लिक स्कूल, हरदोई में आयोजित ऊर्जा आत्मनिर्भरता अभियान संगोष्ठी में स्वावलंबी भारत अभियान एवं स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सतीश कुमार ने व्यक्त किए। अध्यक्षता राजीव मोहन अवस्थी ने की। कवि श्याम त्रिवेदी पंकज और शिक्षक राजकुमार सिंह ने स्वदेशी गीत गाकर स्वदेशी अपनाने का आवाहन किया। वक्ताओं में हर्षवर्धन सिंह, विमलेश दीक्षित, पवन जैन, अशफाक हुसैन, संजीव खरे, अवनीश द्विवेदी ने स्वदेशी अपनाओ और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने और इस वैश्विक संकट पर छोटे–छोटे कार्यों में ऊर्जा बचाकर देश की प्रगति में समृद्धि लाने में सहयोग की अपील की। प्रांत समन्वयक हर्षवर्धन सिंह ने आए हुए लोगों का आभार जताया। अध्यक्षीय उद्‌बोधन के बाद गोष्ठी का समापन किया गया।

सौर ऊर्जा और स्वदेशी से ही दूर होगा ऊर्जा संकट

आज पूरा विश्व एक बेहद गंभीर ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे सीमित संसाधनों पर हमारी बढ़ती निर्भरता आर्थिक और पर्यावरणीय मोर्चे पर नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। इन हालातों के बीच भारत को अगर महाशक्ति बनना है, तो उसे स्वदेशी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने होंगे।

यह गंभीर विचार स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित 'ऊर्जा संकट और समाधान' विषयक विचार गोष्ठी में उभरकर सामने आए। कलेक्ट्रेट रोड (सीतापुर) पर आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने ऊर्जा संरक्षण, स्वदेशी संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का खाका खींचा। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड के क्षेत्र संयोजक अनुपम श्रीवास्तव और जिला संयोजक मुकेश अग्रवाल ने विचार व्यक्त किये।

इस मौके पर मंदीप तिवारी, अमित श्रीवास्तव, रामकुमार शुक्ला, सरवन बंसल, सुरेश भारती, आशीष बघेल, मोहित शुक्ला, आकाश राठौर, सुनील ठंसल, सरवन गुप्ता, अशोक मिश्रा, आनंद दीक्षित, अनुज श्रीवास्तव, विजय मिश्रा, कुलदीप मिश्रा, पवन शुक्ला, गुलाब चंद्र पांडे, सौरभ मिश्रा, सुमित बाजपेई, रमेश मिश्रा, केडी निषाद, नीरज तिवारी और आचार्य राकेश शास्त्री सहित अनेकों प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे।

युवा नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें

स्वदेशी जागरण मंच के जिला वर्ग की ओर से मानव विकास भवन (कोटा) में ऊर्जा आत्मनिर्भरता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन स्वदेशी, स्वावलंबन और ऊर्जा संरक्षण विषयों पर केंद्रित रहा। प्रांत के सहसंयोजक राजेश गौतम ने स्वदेशी की विकास यात्रा और इसके माध्यम से देश में हुए परिवर्तनों की जानकारी दी। स्वावलंबी भारत अभियान राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय समन्वयक एवं मुख्य वक्ता लोकेंद्र सिंह नरूका ने राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए स्वावलंबन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे 'नौकरी पाने वाले के बजाय नौकरी देने वाले' बनें, ताकि राष्ट्र की प्रगति में सार्थक योगदान दे सकें। विभाग संयोजक राजेंद्र सिंह ने कोटा महानगर में स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए टीम की घोषणा की। यह टीम आगामी सत्र में स्वावलंबन विषय पर कार्य करेगी तथा स्वदेशी मेले के माध्यम से मातृ शक्ति और युवा शक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगी। टीम में नीलम विजय, ममता तिवारी, आयुष त्यागी, देवेंद्र सोलंकी, सीमा हाड़ा, रचना गोयल, हेमंत छंदक, डॉ. राजेश दाधीच, सीमा सिंह, जसवंत सिंह सोलंकी और बाबूलाल मेरोठा शामिल हैं। कार्यक्रम में राजेंद्र शर्मा, बूंदी जिले से हरिराज सिंह हाड़ा तथा कमलेश अपनी टोली सहित उपस्थित रहे।

स्वदेशी अपनाने से देश की संपत्ति देश के अंदर रहेगीः जगदीश पटेल

स्वदेशी चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वदेश जागरण मंच द्वारा 31 मई को कस्तूरबा भवन (राजनांदगांव) में पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें जिले भर के स्वदेशी प्रेमी लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तीन सत्रों में चले उक्त कार्यक्रम को रायपुर से पधारे स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय

संयोजक श्री जगदीश भाई पटेल ने कहा कि स्वदेशी केवल नारा नही राष्ट्रहित की नीति है। जो राष्ट्र अपने अर्थ नीति का नियंत्रण रखता है। वहीं राष्ट्र सफल होता है। जब उसका उपभोक्ता जागरूक होगा। वही राष्ट्र भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकता है। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व जिला संयोजक विष्णु साव (अधिवक्ता) ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से रोजगार सृजन होगा। विशेषकर ग्रामीण व कुटीर उद्योग को इसका बहुत लाभ मिलता है और हाथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। कार्यक्रम को स्वदेशी जागरण मंच के करनैल सिंह भाटिया ने भी संबोधित किया। वहीं विधिवत संचालन अमितेश राय मोना गोसाईं द्वारा किया गया।

स्वदेशी, स्वावलंबन और ऊर्जा संरक्षण का लिया संकल्प

स्वदेशी जागरण मंच का जिला विचार वर्ग चौमूं. आदर्श विद्या मंदिर, थाना मोड़ पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्वदेशी, स्वावलंबन और ऊर्जा संरक्षण को जन–जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। उद्घाटन अनाज मंडी व्यापार मंडल के संरक्षक नंदकिशोर कूलवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला संयोजक देवदत्त शर्मा ने मंच की स्थापना एवं विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। प्रांत मंत्री डॉ. सांवरमल सोलेट ने दत्तोपंत गड़ी के विचारों की जानकारी दी। शिक्षाविद नवीन कुमार शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वदेश प्रेम पर विचार रखे। जिला प्रचार प्रमुख शंकरलाल जांगिड़ ने बाबू गेनू के बलिदान को याद किया। द्वितीय सत्र में प्रांत विचार प्रमुख धर्मेद्र शर्मा पुरुषोत्तम ने स्वावलंबी भारत अभियान, उद्यमिता और कौशल विकास की आवश्यकता बताई। समापन सत्र में प्रदेश प्रचार प्रमुख एडवोकेट सुदेश सैनी ने ऊर्जा संरक्षण को राष्ट्रभक्ति से जोड़ते हुए संसाधनों के संयमित उपयोग का आह्वान किया। मुख्य अतिथि डॉ. सुरेंद्र शेरावत ने स्वास्थ्य में स्वदेशी की भूमिका बताई।

हमारा लक्ष्य हर युवा को रोजगार: डॉ राजेश गोयल

स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबन भारत अभियान द्वारा पंचकूला के सेक्टर–7 स्थित डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में "जिला विचार वर्ग" का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ग में स्वदेशी शोध संस्थान के कार्यकताओं, प्रबुद्ध जनों और नव– जिज्ञासुओं सहित कुल 134 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में डॉ. राजेश गोयल जी, संजीव अग्रवाल जी एवं रजनीश जी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में जिला समन्वयक श्री अरुण, डॉ सुल्तान सिंह, रोहित, राकेश अशोक, डॉ. पुनीत बेदी जी, टी. एन. सैनी जी, पीयूष पुंज जी, मयूर जी, दिनेश जी, विकास जी, प्यारे लाल जी सहित जिले के अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं कार्यकताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही।

स्वदेशी जागरण मंच का जिला विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग संपन्न

स्वदेशी जागरण मंच (मंदसौर) द्वारा आयोजित जिला विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग केशव नगर स्थित समर्पण संघ कार्यालय के सभागार में संपन्न हुआ। जिसमें स्वदेशी विचारधारा, आत्मनिर्भर भारत, स्थानीय उद्योगों के संवर्धन, रोजगार सृजन, कृषि विकास एवं संगठन विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उद्घाटन सत्र में प्रांत सह–संयोजक श्री दिलीप सिंह चौहान ने स्वदेशी विकास यात्रा विषय पर मार्गदर्शन देते हुए कहा कि स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास एवं आत्मनिर्भरता का माध्यम है। प्रांत पूर्णकालिक श्री हेमंत रावत, विभाग संयोजक श्री दिलीप व्यास, विभाग सह–संयोजक श्री अंकुश पालीवाल, जिला संयोजक श्री दिलीप चौधरी मंचासीन रहे। दुर्गावाहिनी प्रमुख श्रीमती टीना शर्मा ने स्वदेशी जीवनशैली व राष्ट्र निर्माण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। जिला सह संयोजक श्री महेंद्र सिंह राजावत ने स्वदेशी आंदोलन के अमर सेनानी शहीद बाबू गेनू के जीवन एवं उनके राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत योगदान पर प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। सत्र की अध्यक्षता विभाग संयोजक श्री दिलीप व्यास ने की।

सत्र की अध्यक्षता सीआरपीएफ से सेवानिवृत उप निरीक्षक श्रीमती उषा कुमावत ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन तहसील युवा आयाम प्रमुख श्री अभिजीत सिंह चौहान ने किया, जबकि जिला संपर्क प्रमुख डॉ. हेमंत नामदेव ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर तहसील संयोजक श्री अभिजीत सिंह मंडलोई, वरिष्ठ आयाम प्रमुख श्री वीरेंद्र आर्य, सीए गजेंद्र आंजना, रेखा जोशी, विजयलक्ष्मी सांखला, अलका गर्ग, आशा कोठारी, शशि झलौया, ज्योति परमार, भरत ओझा, सतीश बैरागी, कनिष्क शर्मा, हरिराम प्रजापत, निलेश पोरवाल, विश्वास शर्मा, महेश संगतानी, नारायण कोटवानी, संदीप पुरोहित, चंदन शर्मा, बालकृष्ण सूर्यवंशी, सूरज रावल, बाबू प्रजापत, आशीष मीणा, लक्की सिंह, प्रदीप कुमार, देवीलाल, रमेश कुमार, रविन्द्र सिंह जादौन, कैलाश साखला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, उद्यमी, शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

जिला विचार/प्रशिक्षण वर्ग

सचित्र झलक

भुवनेश्वर, उड़ीसा

जमशेदपुर, झारखंड

पूर्व मेदिनीपुर, मध्य बंग

अगरतला, त्रिपुरा

झुंझुनू

उत्तर बस्तर, छत्तीसगढ़

जोधपुर, राजस्थान

चाईबासा, झारखंड

देवास, मालवा

पुरी, उड़ीसा

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जून 2026
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

जिला विचार/प्रशिक्षण वर्ग

सचित्र झलक

छत्तीसगढ़

वाशिम, महाराष्ट्र

बालेश्वर, उड़ीसा

चंडीगढ़

डिब्रूगढ़, असम

उज्जैन, मालवा

सिलीगुड़ी, उत्तर बंग

पटना, बिहार

बोकारो, झारखंड

कडपा, आंध्र प्रदेश

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती